



**स्टार्ट-अप...** (पेज एक का शेष) हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्ट, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम जैसे शहर स्टार्ट-अप के केंद्र बन रहे हैं तो मन आनंद से भर जाता है। मोदी ने कहा, "अपशिष्ट प्रबंधन, गैर-नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स ऐसे क्षेत्र हैं, जिनसे जुड़े स्टार्ट-अप सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। ये पारंपरिक क्षेत्र नहीं हैं लेकिन हमारे युवा-साथी भी तो परंपरा से आगे की सोच रखते हैं, इसलिए, उन्हें सफलता भी मिल रही है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले जब कोई स्टार्ट-अप की बात करता था तो उसे तरह-तरह के ताने सुनने को मिलते थे और लोग कहते थे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, "लेकिन अब देखिए, एक दशक में कितना बड़ा बदलाव आ गया।" प्रधानमंत्री ने इस दौरान स्वामी विवेकानंद की चर्चा की और उल्लेख किया कि उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति में अपने विचारों के प्रति जुनून होता है, वही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी विचार को सफल बनाने के लिए जुनून सबसे जरूरी होता है और निष्ठा तथा उत्साह से नवाचार, सृजनत्मकता और सफलता का रास्ता अवश्य निकलता है। प्रधानमंत्री ने अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य के जुड़ाव के संबंध में कहा कि भारतीय संस्कृति और विरासत आसपास के पशु-पक्षियों के साथ प्यार से रहना सिखाती है। उन्होंने असम के नौगांव का उदाहरण दिया, जहां ग्रामीणों ने हाथियों के भोजन लिए 800 बीघा परती भूमि पर नेपियर घास उगाई है। मोदी ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य और मध्यप्रदेश में रातापानी बाघ अभयारण्य की स्थापना पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान को याद करते हुए 23 जनवरी को उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का उल्लेख किया और युवाओं से अपील की कि वे नेताजी के बारे में अधिक से अधिक पढ़ें और उनके जीवन से निरंतर प्रेरणा लें। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दीपक नाबाम की चर्चा की जो एक ऐसा लिविंग-रूम चलाते हैं जहां शारीरिक और मानसिक दिव्यांगों के अलावा बुजुर्गों और नशे के शिकार लोगों की देखभाल की जाती है। उन्होंने लक्षद्वीप के कवारती में कार्यरत नर्स के हिंदुम्बी और के जी मोहम्मद के कार्यों की भी प्रशंसा की। मोदी ने निकोबार जिले में नारियल तेल के लिए जीआई-टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इस तेल के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं के स्व-सहायता समूह बनाए जा रहे हैं और उन्हें इस तेल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, "ये हमारे आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में निकोबार का यह तेल दुनिया-भर में धूम मचाने वाला है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अंडमान और निकोबार के महिला स्व सहायता समूह का होगा।"

**यहुल गांधी...** (पेज एक का शेष) करते हैं, संपत्ति की बढ़ती असमानताओं का विरोध करते हैं, सामाजिक समानता के लिए लड़ते हैं, सभी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार करते हैं और हमारे देश में शांति एवं स्थिरता के लिए प्रयासरत हैं, तो सफेद टी-शर्ट पहनें और मुहिम में शामिल हों। गांधी ने कहा, "आज मोदी सरकार ने गरीबों और श्रमिक वर्ग से मुंह मोड़ लिया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को और समृद्ध बनाने पर है।" उन्होंने कहा कि इसके कारण असमानता लगातार बढ़ रही है और "अपने खून-पसीने से देश को सींचने वाले" श्रमिकों की स्थिति खराब होती जा रही है और वे विभिन्न प्रकार के अन्याय और अत्याचार सहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा, "ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें न्याय और अधिकार दिलाते के लिए आवाज उठाएं। इसी सोच के साथ हम 'सफेद टी-शर्ट मुहिम शुरू कर रहे हैं।" कांग्रेस सांसद ने कहा, "ये युवाओं और मजदूर वर्ग के साथियों से इस मुहिम में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील करता हूँ।" उन्होंने लोगों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल नंबर और एक वेबसाइट का लिंक भी साझा किया। 'व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट' (सफेद टी-शर्ट मुहिम) की वेबसाइट के अनुसार, 'सफेद टी-शर्ट' पार्टी के पांच मार्गदर्शक सिद्धांतों — करुणा, एकता, अहिंसा, समानता और सभी के लिए प्रगति — का प्रतीक है।

**दिल्ली विधानसभा...** (पेज एक का शेष) गारंटो को अपना मजबूत समर्थन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने 'पीटीआई-भाषा' को दिये साक्षात्कार में इस बात पर जोर दिया कि इन योजनाओं का उद्देश्य वंचितों को समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हर सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करे। पिछले 10 वर्षों में, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ने के कारण महिलाओं को अपना घर चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी चिंताओं का समाधान करें, ताकि वे अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें।" यादव ने कहा, "ऐसी स्थिति में मैं इसे मुफ्तखोरी या रेवड़ी नहीं कहूंगा, यह उनका अधिकार है। यह उनका अधिकार है, क्योंकि संविधान में वंचितों को समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान है और ये योजनाएं उन्हें उचित अवसर प्रदान करने का एक साधन हैं।" उन्होंने कहा कि इस दिशा में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पांच गारंटो सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिनमें महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और राशन किट तथा 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने के एक साल से भी कम समय में यह दूसरा चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनौतियां अलग थीं और उस वक्त उनके पास पंजाब का भी प्रभार था। उन्होंने कहा, "उस समय मेरे पास सीमित दायरा था, और हमने उस समय पूरी कोशिश की। चुनाव के बाद, हमने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से हम अब बेहतर स्थिति में हैं। हम ब्लॉक और जिला स्तर पर गए, अपने संगठन को बेहतर बनाया और लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई।"

**आइये कुछ...** (पेज एक का शेष) घुटनों से भी नीचे हो जाते हैं और उन्हें (उन महिलाओं को) यदि छोटे बाल पसंद हों तो बालों को बार-बार कटवाना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। बार-बार ब्यूटीपार्लर के चक्कर लगाना वे पसंद नहीं करेंगी। उनके बाल और न बढ़ें, इनके लिए वे बालों की देखभाल करना बंद कर देंगी। शायद इससे उनके बालों की चमक ही खो जाये और बाल बढ़ने फिर भी कम न हों। प्राकृतिक बाल जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। धोड़ी-सी लापरवाही से आप उनकी सुंदरता भी खो बैठेंगी। किसी भी प्राकृतिक चीज को आप बदल नहीं सकती मगर आप उसे संवार जरूर सकती हैं। यदि आपके बाल रूखे हैं तो बालों को प्राकृतिक तेल में डुबो कर मालिश करें। यदि आपके बाल सामान्य हैं तो उन्हें हफ्ते में एक बार तेल लगायें और यदि आपके बाल तैलीय हैं तो भी अपने बालों में कमी-कमी तेल लगाना न भूलें। हां, बालों को तेल में तर तमी करें जब वे नार्मल या रूखे हों, तैलीय नहीं। उसी शैली और उसी तेल का इस्तेमाल करें जो आपके बालों के अनुकूल हो। यदि आपके बाल झड़ते हैं तो इसका इलाज कोई दवाई, खास शैली या साबुन नहीं बल्कि संतुलित भोजन है। भोजन में यदि आप प्रोटीन संतुलित मात्रा में लेती हैं तो आपके बालों का झड़ना निश्चित ही कम हो जायेगा। बालों को भी भोजन की जरूरत होती है और उनका भोजन है प्रोटीन। बाल क्योंकि निर्जीव होते हैं, सो जरूरी है उन्हें ज्यादा देखभाल की। आप अगर बालों को ज्यादा कधी करेंगी तो बाल झड़ेंगे ही। बालों में रूसी और बालों का सफेद होने का कारण संतुलित भोजन की कमी है। अपने बालों को गंदा न होने दें। सप्ताह में दो बार बालों को जरूर धोएं। बालों में रोज कधी करें। इससे बालों की गंदगी दूर होगी। बालों पर ज्यादा समय के लिए स्कार्फ भी नहीं ओढ़े रहना चाहिए। इससे बालों के टूटने की समस्या ज्यादा बन जाती है। बालों की साफ-सफाई से भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर क्यों नहीं पारंगी आप लहराते हुए बाल।

**केजरीवाल ने...** (पेज एक का शेष) कठिनाइयों का जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि वे सम्मान के साथ रहें। केजरीवाल ने कहा कि प्रस्तावित योजना को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के कर्मचारियों के साथ शुरू किया जा सकता है तथा उसके बाद इस योजना को दिल्ली के सभी सरकारी कर्मचारियों तक विस्तारित किया जा सकता है। 'आप' सुप्रीमो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि सत्ता में लौटने के बाद 'आप' केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि पर किरायेती आवास इकाइयों का निर्माण करेगी क्योंकि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी कोई भूमि नहीं है। केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली में खासकर गरीबों के लिए आवास एक बड़ी समस्या है। घर का मालिक होना या किराए पर रहना लगभग असंभव है।" उन्होंने कहा, "उनकी (सरकारी कर्मचारियों की) पेंशन किराए के घर का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है और न ही उनके पास अपने लिए घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं।" पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने कई सफाई कर्मचारियों को देखा है, जो सेवानिवृत्ति के बाद झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हैं।" केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस योजना को शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, "इसकी शुरुआत एनडीएमसी और एमसीडी के सफाई कर्मचारियों से की जा सकती है, जो अपने सेवा काल के अंतिम चरण के दौरान आसान किश्तों का भुगतान करके इसका लाभ उठा सकते हैं।" 'आप' संयोजक ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इस योजना पर सहमत होंगे क्योंकि यह गरीबों के कल्याण के लिए है। केजरीवाल ने कहा, "शुरुआत में इसका लाभ सफाई कर्मचारियों को मिलेगा और बाद में इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों तक भी पहुंचाया जा सकता है। यह पूरी तरह से कल्याणकारी योजना है।"

**महाकुंभ का...** (पेज एक का शेष) संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई, संस्कृत के मंत्रों, अवधी की चौपाइयों, सनातन धर्म से जुड़े स्त्रोत और मंत्रों को सरस्वर गा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां गंगा और यहां के धामों के प्रति एक श्रद्धा का भाव उनमें देखने को मिल रहा था। आदित्यनाथ ने कहा, "महाकुंभ के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के मुख्य स्नान संपन्न हो चुके हैं और अब मौनी अमावस्या 29 जनवरी और बसंत पंचमी तीन फरवरी को दो बड़े महान्दान होने हैं।" उन्होंने कहा कि सात हजार से अधिक संस्थाएं अब तक यहां पर आ चुकी हैं और आज पूरे महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नानार्थियों और यहां रह रहे कल्याणियों के साथ ही अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों की पूरी संख्या देखेंगे तो लगभग एक करोड़ से अधिक लोग यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा, "इन्हीं सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यहां भेजा था।" मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और मां गंगा की कृपा से हम लोग यहां पर इन दोनों स्नानों को सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे।" आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा, "कई राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री लगातार यहां आ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भी लगातार यहां आकर स्नान कर रहे हैं।" मुख्यमंत्री ने कहा, "मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के दिन हमें यह सौभाग्य नहीं मिल सका कि हम भी यहां स्नान कर सकें, क्योंकि हम लोगों ने खुद को प्रतिबंधित कर रखा था। केवल संतों और श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा थी।"

## हजारों लोगों ने नागा साधुओं के अखाड़ों में शामिल होने को आवेदन किया

**महाकुंभ नगर, (भाषा)** सनातन धर्म की रक्षा के लिए हजारों लोगों ने नागा साधु के तौर पर दीक्षा लेने के लिए अखाड़ों में आवेदन किया है और तीन स्तरों पर इन आवेदनों की जांच कर दीक्षा देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निरंजनी अखाड़ा के महंत रवींद्र पुरी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि निरंजनी में प्रथम चरण में 300-400 लोगों को नागा संन्यासी के तौर पर दीक्षा दी जा रही है और 13 अखाड़ों में सात शैव अखाड़े हैं, जिनमें से छह अखाड़ों में नागा साधु के तौर पर दीक्षा दी जाती है। उन्होंने बताया कि इनमें निरंजनी, आनंद, महानिवाणी, अटल, जूना और आटवान अखाड़ों में नागा साधु बनाए जाते हैं जबकि अग्नि अखाड़े में ब्रह्मचारी होते हैं, वहां नागा नहीं बनाए जाते हैं। शंकराचार्य ने नागा साधु बनाने की जो परंपरा डाली थी, वह संन्यासी अखाड़ों के लिए है। जूना अखाड़ा के महामंत्री हरि गिरि महाराज ने बताया कि जूना अखाड़े में नागा साधुओं को दीक्षा के लिए जगह का अभाव है, इसलिए कई चरणों में इन्हें नागा साधु की दीक्षा दी जाएगी और हजारों की संख्या में नागा साधु के लिए आवेदन आए हैं। महानिवाणी अखाड़े के सचिव महंत यमुनापुरी महाराज ने बताया कि महानिवाणी में 300-350 लोगों को नागा साधु के तौर पर दीक्षा दी जा रही है जिसके लिए पहले से काफी लोगों के आवेदन आए थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि विभिन्न अखाड़ों में नागा साधु के तौर पर दीक्षा के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने आवेदन कर रखा है जो सनातन धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके नागा साधु बनना चाहते हैं। एक आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परीक्षा जारी की जा रही है, साथ ही गोपनीय ढंग से आवेदकों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं, सभी पात्रता पूरी करने वाले लोगों को ही नागा साधु के तौर पर दीक्षा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी के किनारे नागा साधुओं के संस्कार किए जा रहे हैं, इसमें मुंडन संस्कार और पिंडदान शामिल है, ये संन्यासी अपना स्वयं का पिंडदान कर यह घोषणा करते हैं कि उनका भौतिक दुनिया से अब कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सभी अनुष्ठान के बाद मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के साथ नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। महामंडलेश्वर ने बताया कि ये सभी लोग धर्म ध्वजा के नीचे नगनावस्था में खड़े होंगे और आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें नागा बनने की दीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि समापति उन्हें अखाड़े के नियम आदि बताएंगे और उन्हें नियमों का पालन करने की शपथ दिलाएंगे, यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर किसी को अमृत स्नान के लिए भेजा जाएगा। एक अन्य अखाड़े के महंत ने बताया कि ऐसा नहीं है कि हर उम्मीदवार को नागा साधु बनाया जाएगा क्योंकि जांच के दौरान कई लोग अपात्र पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीन चरणों में आवेदनों की जांच की गई और यह प्रक्रिया छह महीने पहले शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि अखाड़ा के थानापति ने उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और गतिविधियों की जांच की और इसकी रिपोर्ट आचार्य महामंडलेश्वर को दी गई और आचार्य महामंडलेश्वर ने अखाड़े के पंचों से पुनः इसकी जांच कराई जिसके बाद ही नागा साधु बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

## ओमान के साथ एफटीए में शराब, सिगरेट पर

**शुल्क रियायत नहीं मांग रहा भारत: सूत्र**  
**नयी दिल्ली, (भाषा)** ओमान के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में भारत शराब और सिगरेट जैसे 100 से अधिक उत्पाद श्रेणियों पर सीमा शुल्क रियायत की मांग नहीं कर रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारत और ओमान के बीच एफटीए पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि एफटीए वार्ताएं संपन्न हो गई हैं, ओमान ने कुछ उत्पादों पर अपने बाजार पहुंच प्रस्तावों में संशोधन की मांग की है।

# FOCUS NEWS



Scan Barcode or QR Code to Download the App



## महाराष्ट्र में 60 लाख परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा : फडणवीस



प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। फडणवीस ने कहा कि ये प्रमाण पत्र न केवल स्वामित्व के प्रमाण के रूप में काम करते हैं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा करते हैं। स्वामित्व योजना के तहत ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों – छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों के लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं।

### सोनोवाल करेंगे मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन



मुंबई, (भाषा) मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का तीसरा संस्करण 22 जनवरी से यहां शुरू होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन उद्योग मंडल फेडरेशन फिक्की कर रहा है। भारतीय बंदरगाह संघ द्वारा समर्थित इस परियोजना में स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के माध्यम से बंदरगाहों में बदलाव सहित प्रमुख रणनीतिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस आयोजन में समुद्री क्षेत्र के 7,500 से अधिक लोगों के आने का अनुमान है।

### कैदियों के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए जेल प्रशासन में सुधार की जरूरत: न्यायालय

नयी दिल्ली, (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कारागार में बेहतर माहौल के लिए जेल प्रशासन में सुधार की जरूरत है ताकि कैदियों को संविधान के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 'फ्योदोर दोस्तोवस्की' की प्रसिद्ध पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा, 'किसी समाज में सभ्यता का अंदाजा उसकी जेलों में प्रवेश करके लगाया जा सकता है।' पीठ ने कैदियों के साथ सम्मान और मानवीय परिस्थितियों के अधिकार वाले मनुष्य के रूप में व्यवहार करने के महत्व को रेखांकित किया। पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज करते हुए की। उच्च न्यायालय ने विकास तिवारी नाम के एक अपराधी को राज्य के एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने के फैसले को रद्द कर दिया था। पीठ ने जेल सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित गिरोह हिंसा को रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हुए जेल महानिरीक्षक के आदेश को बहाल कर दिया। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने भारत के जेल प्रशासन में प्रणालीगत कमियों को रेखांकित किया और कैदियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया।

## उत्तर प्रदेश: हस्तशिल्पियों के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित हो रहा महाकुम्भ



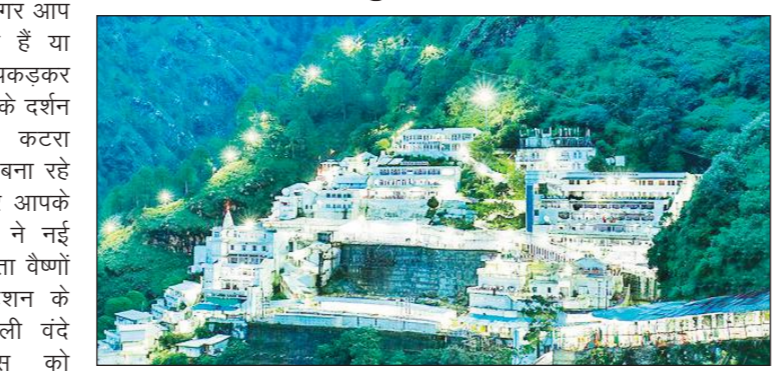
महाकुम्भ नगर, (भाषा) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ मेला राज्य के हस्तशिल्पियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो रहा है। मेला क्षेत्र के लगभग छह हजार वर्ग मीटर में लगाई गई 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) प्रदर्शनी में कालीन, जरी-जुदोजी का काम, फिरोजाबाद के कांच के खिलौने और वाराणसी के लकड़ी के खिलौने समेत कई बेहतरीन हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जा रहे हैं। प्रयागराज मंडल में संयुक्त उद्योग आयुक्त शरद टंडन ने बताया कि 2019 में आयोजित पिछले कुम्भ की तुलना में कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। टंडन ने बताया, "2019 में 4.30 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था लेकिन इस बार हमें 35 करोड़ रुपये तक के कारोबार की उम्मीद है। यह उल्लेखनीय वृद्धि योजना के नये अवसर प्रदान करेगी और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाएगी।" ई-कॉमर्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी 'फ्लिपकार्ड' ने एक स्टॉल लगाया है, जहां स्थानीय उद्यमियों को मुफ्त बिक्री का अवसर दिया जा रहा है। कारीगर और हस्तशिल्प विक्रेता अब बिना किसी शुल्क के फ्लिपकार्ड के मंच पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं, जो बड़ी संख्या में खरीदारों और आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है। प्रदर्शनी विभिन्न शिल्प और भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी सामने लाती है। जीआई विशेषज्ञ रजनीकांत ने बताया कि इस पहल के तहत राज्य के 75 जीआई उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें वाराणसी की लाल मिर्च, बनारसी साड़ियां, प्रतापगढ़ का आंवला, मिर्जापुर के पीतल के बर्तन और गोरखपुर का टेराकोटा शामिल हैं। इसके अलावा, कुशीनगर के कालीन, फिरोजाबाद के कांच के खिलौने और बर्तन प्रदर्शनी के शीर्ष आकर्षणों में से हैं। उन्होंने बताया कि इन 75 जीआई उत्पादों में से 34 काशी क्षेत्र के हैं, जिसने इन अद्वितीय शिल्पों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करते हुए जीआई टैग हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रजनीकांत ने बनारस की ठंडाई, लाल पेड़ा और बनारसी तबला जैसे अन्य प्रतिष्ठित उत्पादों को वैश्विक मंच पर लाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। महाकुम्भ न केवल क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है बल्कि उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मंच भी बनाता है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटक स्थानीय कारीगरों से उत्पाद खरीद रहे हैं, जो इन दस्तकारी उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता को जाहिर करता है।

## एनआईटी राउरकेला ने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि के लिए नयी कैथोड प्रौद्योगिकी विकसित की

नयी दिल्ली, (भाषा) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला के अनुसंधानकर्ताओं ने लिथियम-आयन बैटरी के लिए कैथोड सामग्री की एक नयी श्रेणी विकसित की है, जो कोबाल्ट-आधारित डिजाइन का एक आशाजनक विकल्प पेश करती है। यह नवाचार पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरी में एक प्रमुख घटक कोबाल्ट की उच्च लागत, कमी और पर्यावरणीय चिंताओं से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करेगा। अनुसंधान टीम ने कोबाल्ट के टिकाऊ और कफायती विकल्प के रूप में मैग्नीशियम आधारित कैथोड सामग्री विकसित की है। एनआईटी राउरकेला में सिरिमिर्क इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर पार्थ साहा ने कहा कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) जैसे उपकरणों को उच्च प्रदर्शन वाले लिथियम-आयन बैटरी में मुख्य रूप से कोबाल्ट आधारित कैथोड का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि, कोबाल्ट कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिनमें इसकी उच्च लागत और मूल्य अस्थिरता तथा सीमित उपलब्धता आदि शामिल हैं। साहा ने कहा, "लिथियम-आयन बैटरी की मांग बढ़ती जा रही है। ये मुझे लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2050 तक कोबाल्ट की वैश्विक आपूर्ति बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पाएगी, जिससे वैकल्पिक सामग्री विकसित करने की तत्काल आवश्यकता को बल मिलता है।" मैग्नीशियम के कई लाभ हैं। यह सस्ता है और भारत में प्रचुर मात्रा में व्यापक रूप से उपलब्ध है। तमिनाडु, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसके महत्वपूर्ण भंडार हैं। इसके अतिरिक्त, मैग्नीशियम पर्यावरण के अनुकूल है जो बैटरी उत्पादन के पारिस्थितिकी प्रभाव को कम करने में मदद करता है। साहा ने कहा, "हमारे अनुसंधान से पता चलता है कि नए कैथोड में 100 'चार्ज-डिस्चार्ज' चक्रों के बाद इसकी मूल क्षमता का 74.3 प्रतिशत बरकरार रहता है, जो पारंपरिक कोबाल्ट-आधारित कैथोड में देखी गई तीव्र क्षमता हानि की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है।" उन्होंने बताया कि इस सफलता के व्यापक निहितार्थ और अनुप्रयोग हैं तथा यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सस्ती और उच्च प्रदर्शन वाली बैटरी बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे बढ़ते ईवी उद्योग में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। साहा ने कहा, "इसके अतिरिक्त, यह सतत विकास के लिए आवश्यक कफायती ऊर्जा भंडारण समाधान उपलब्ध कराकर भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करेगा। आयातित सामग्री पर निर्भरता को कम करके यह नवाचार बैटरी उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगी जिससे वैश्विक निर्यात बाजार में देश की स्थिति मजबूत होगी।"

मुंबई, (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि स्वामित्व योजना से राज्य के 60 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना की संकल्पना राष्ट्रीय प्रगति की नींव के रूप में ग्रामीण विकास के महत्व को मान्यता देते हुए की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री फडणवीस महानगर के सह्याद्री गेस्ट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फडणवीस ने कहा, "यह पहल केवल एक सरकारी परियोजना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व को लेकर अनिश्चितता और विवाद कम होंगे।" उन्होंने कहा, "भूमि का स्वामित्व साबित करना अक्सर कठिन हो जाता है, जिससे कानूनी मामलों में वृद्धि होती है और विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। स्वामित्व योजना इन चुनौतियों का समाधान करेगी। इस योजना के तहत, गांवों में भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है, और व्यक्तियों को कानूनी स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। फडणवीस ने कहा कि ये प्रमाण पत्र न केवल स्वामित्व के प्रमाण के रूप में काम करते हैं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा करते हैं। स्वामित्व योजना के तहत ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों – छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों के लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं।

### नई दिल्ली से वैष्णों देवी जाने वालों को अगले कुछ दिनों तक होगी असुविधा, जानिए क्यों



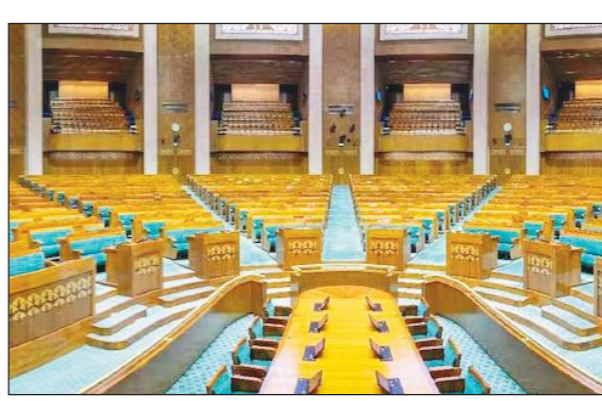
नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से ट्रेन पकड़कर माता वैष्णों देवी के दर्शन करने के लिए कटरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे ने नई दिल्ली से श्रीमाता वैष्णों देवी कटरा स्टेशन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को अगले 50 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया है। आज यानी 16 जनवरी से 6 मार्च 2025 तक वंदे भारत ट्रेन संख्या (22439/40) रद्द रहेगी। रेलवे ने इसके पीछे जम्मू तवी यार्ड के रीमॉडलिंग का कारण बताया है। हालांकि यात्रियों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी वंदे भारत ट्रेन जिसका नंबर (22477/78) है वो सुचारु रूप से चलती रहेगी। अभी नई दिल्ली से कटरा और कटरा से नई दिल्ली के लिए बुधवार के दिन छोड़कर पूरे हफ्ते दो वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं। इनमें से ट्रेन संख्या (22439/40) को रद्द कर दिया है। ट्रेन संख्या 22439 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे चलकर दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर श्रीमाता वैष्णों देवी कटरा स्टेशन पहुंचती है। अंबाला कैंट, लुधियाना, पठानकोट और जम्मू तवी स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव है। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 22440 दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर श्रीमाता वैष्णों देवी कटरा स्टेशन से चलकर रात 11 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। रेलवे ने इस ट्रेन की दोनों को रद्द कर दिया है। नई दिल्ली से वैष्णों देवी जाने और वहां से वापसी के लिए फिलहाल अब एक ही वंदे भारत ट्रेन संख्या (22477/78) बची है। ट्रेन संख्या 22478 सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर कटरा स्टेशन से छूटकर दोपहर 2 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। नई दिल्ली से ट्रेन संख्या 22477 दोपहर 3 बजे छूटती है और रात 11 बजकर 15 मिनट पर कटरा पहुंचती है। इस ट्रेन के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उधर, माता वैष्णों देवी के रास्ते में इस मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ की फुहारों के बीच श्रद्धालु माता रानी के दर्शन को भवन पहुंच रहे हैं।

### पद्म पुरस्कार से सम्मानित ओडिशा के लोगों को 30,000 रुपये का मासिक मानदेय मिलेगा

मुवनेश्वर, (भाषा) ओडिशा सरकार पद्म पुरस्कार से सम्मानित राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को इस महीने से 30,000 रुपये का मासिक मानदेय प्रदान करेगी। ओडिशा भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग ने बृहस्पतिवार को इस संघर्ष में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में समाज के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को 30,000 रुपये का मानदेय प्रदान करने का निर्णय लिया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मार्च 2024 में पूर्ववर्ती बीजद सरकार ने 25,000 रुपये मासिक मानदेय की घोषणा की थी। हालांकि, इसे अब तक लागू नहीं किया गया है।

## संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी के बीच होने की संभावना

नयी दिल्ली, संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी के बीच होने की संभावना है। इस दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। परंपरा के अनुरूप सत्र की शुरुआत संभवतः 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके बाद एक फरवरी सीतारमण लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। सूत्रों ने बताया कि सत्र का दूसरा भाग मार्च के दूसरे सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच होगा। इसकी संभावित अवधि 10 मार्च से 4 अप्रैल तक हो सकती है। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में बहस होती है और संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के जवाब के साथ यह समाप्त होता है।



## दिल्ली चुनाव: भाजपा के मालवीय नगर प्रत्याशी ने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 'विकास की रूपरेखा' जारी की

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर से उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने शुक्रवार को निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी 'विकास की रूपरेखा' जारी की। इस 'विकास की रूपरेखा' में स्थानीय मुद्दों के लिए एकल खिड़की समाधान, बिजली और पानी के बिल की समीक्षा, कूड़ा हटाने और स्वच्छ पेयजल का वादा किया गया है। भाजपा की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष का मुक़ाबला मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी (आप) के निवर्तमान विधायक सोमनाथ भारती से है। उपाध्याय ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए खुले नालों, जलभराव, सीवेज, यातायात जाम, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के मामले, पार्किंग की सुविधा, सुसज्जित पार्क और राशन कार्ड पंजीकरण को फिर से शुरू करने जैसे मुद्दों को हल करने का वादा किया। उन्होंने कहा, "आम आदमी पार्टी जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही। पानी की आपूर्ति और सीवर की समस्या जैसी बुनियादी समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं। दिल्ली को पेरिस या लंदन जैसा बनाने का सपना अधूरा है, लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।" भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि शहर का बुनियादी ढांचा 'दयनीय' स्थिति में है, टूटी सड़कों और बारिश के दौरान जलभराव आम बात है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। उन्होंने विधानसभा उपाध्याय कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत और डिजिटल भारत के दृष्टिकोण के तहत मालवीय नगर का व्यापक विकास होगा तथा भाजपा 25 साल से अधिक के अंतराल के बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी।



## सातवीं दिल्ली विधानसभा पांच साल में 74 दिन ही चली : रिपोर्ट

नयी दिल्ली, (भाषा) सातवीं दिल्ली विधानसभा अपने पांच साल के कार्यकाल में सिर्फ 74 दिन ही चली, जो पिछली सभी विधानसभाओं की तुलना में सबसे कम आंकड़ा है। यह जानकारी 'थिंक टैंक' पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट में दी गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधानसभा सत्र हर साल बुलाए जाते थे और कई भागों में विभाजित किए जाते थे। प्रत्येक वर्ष, सत्रों को बिना सत्रावसान के स्थगित कर दिया जाता था और उन्हें कई हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता था। रिपोर्ट के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप कई मौकों पर सदन की बैठक सिर्फ एक या दो दिन ही हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपराज्यपाल सत्र बुलाते और स्थगित करते हैं, लेकिन सत्र के दौरान बैठक बुलाने का काम अध्यक्ष का होता है। सातवीं दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 20 फरवरी, 2020 को शुरू हुआ था और पांच भागों में आयोजित होने के बाद तीन मार्च, 2021 को इसका सत्रावसान कर दिया गया था। दूसरा सत्र तीन मार्च, 2021 को शुरू हुआ और चार भागों के बाद आठ मार्च, 2022 को इसका सत्रावसान किया गया। तीसरा सत्र आठ मार्च, 2022 को ही शुरू हुआ और चार भागों में सदन चलने के बाद नौ मार्च, 2023 को इसका सत्रावसान कर दिया गया। चौथा सत्र नौ मार्च, 2023 को बुलाया गया और सात फरवरी, 2024 को इसका सत्रावसान हुआ। इस बार भी चार भागों में ही इसे आहूत किया गया। पांचवां सत्र सात फरवरी, 2024 को आहूत किया गया और अभी तक इसका सत्रावसान नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पांच वर्षों में केवल 14 विधेयक पारित किए गए, जो इसके पिछले सभी कार्यकालों के बाद से सबसे कम संख्या है। चौदह विधेयकों में से पांच विधायकों के वेटन से संबंधित थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी विधेयक या तो उसी दिन या अगले दिन पारित किए गए। कुल 74 दिनों के सत्र के दौरान प्रश्नकाल केवल नौ दिन ही हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2025 के बीच दिल्ली के विधायकों ने हर साल औसतन 219 सवाल पूछे। इसके विपरीत, 2019 से 2024 के बीच लोकसभा में सांसदों ने हर साल औसतन 8,200 सवाल पूछे। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होगा और आठ फरवरी को मतों की गिनती होगी।



सुरक्षा संवर्ग कर्मियों को वेतनमान पर ध्यान दिये बिना रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाये: रेलवे यूनियन

नयी दिल्ली, (भाषा) सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिये जाने के बाद रेलवे यूनियनों के एक वर्ग ने सरकार से रात्रि ड्यूटी भत्ते को लेकर अपने फेसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 13 जुलाई, 2020 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसके अनुसार अन्य शर्तों के साथ-साथ "रात्रि ड्यूटी भत्ते की पात्रता के लिए मूल वेतन की अधिकतम सीमा 43,600 रुपये प्रति माह होगी"। पूर्वोत्तर रेलवे में सत्रावसान के सहायक महासचिव विवेक मिश्रा ने कहा, "डीओपीटी ओएम (कार्यालय ज्ञापन) के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 43,600 रुपये से अधिक है, तो उसको रात्रि ड्यूटी भत्ते (एनडीई) की गिनती उसके मूल वेतन को 43,600 रुपये मानकर की जाएगी, जो अनुचित और तर्कहीन है।" रेलवे बोर्ड ने हालांकि 29 सितंबर, 2020 को एक निर्देश जारी किया था और कहा था कि एनडीई उन कर्मचारियों को ही दिया जायेगा, जो केवल वेतन स्तर सात तक हैं। इससे उच्च वेतन स्तर आठ और नौ के कर्मचारियों को एनडीई का कोई भी लाभ मिलने की संभावना समाप्त हो गई। मिश्रा ने कहा, "रेल मंत्रालय ने भी इस तरह का प्रतिबंध लगाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया। यह हतोत्साहित करने वाला है। क्योंकि सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, मैं डीओपीटी के साथ-साथ रेल मंत्रालय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे इस पहलू पर अलग से विचार करें क्योंकि रेलवे का कामकाज अन्य सरकारी विभागों की तरह नहीं है।" यूनियनों के अनुसार, "2020 से पहले, सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके पदक्रम वेतन की परवाह किए बिना रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच काम करने के लिए उक्त भत्ता मिलता था। लेकिन सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद जब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर अधिकतम सीमा तय कर दी, तो सुरक्षा विभाग के कई कर्मचारी अब एनडीई से वंचित हो गए हैं।" यूनियनों के अनुसार, "सुरक्षा विभाग के महासचिव सुमीर आइमा ने कहा, "एक स्टेशन मास्टर रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक आठ घंटे काम करता है और उसे एनडीई का लाभ मिलता है, क्योंकि वह वेतन स्तर सात में आता है। दूसरी ओर, यदि किसी अन्य स्टेशन मास्टर को स्तर आठ या स्तर नौ में पदोन्नति मिलेगी जाता है, तो उसे समान ड्यूटी घंटे करने के बावजूद लाभ नहीं मिलता, भले ही वह स्तर सात वाले से अधिक अनुभवी क्यों न हो।" अखिल भारतीय रेलगाड़ी नियंत्रक संघ (एआईटीसीए) के पूर्व सहायक महासचिव मनोज सिन्हा ने कहा, "जब वरिष्ठ अधिकारी घर पर सो रहे होते हैं तो ये कर्मचारी लोगों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं।

### सुरक्षा संवर्ग कर्मियों को वेतनमान पर ध्यान दिये बिना रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाये: रेलवे यूनियन

सभी असुरक्षित, सैफ पर हमले ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी : पटोले

मुंबई, (भाषा) कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले ने महाराष्ट्र की 'ध्वस्त' हो चुकी कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है। पटोले ने कहा, "महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल के नेता और नागरिक असुरक्षित हैं। कांग्रेस नेता ने राज्य का गृह विभाग भी संभाल रहे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को 'अप्रभावी' और 'कमजोर' करार दिया और उनसे गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग की क्योंकि राज्य में बढ़ती अपराध दर सरकार की विफलता को दर्शाती है। पटोले ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को खोखले बयान देने के बजाय ठोस कार्रवाई करने का साहस दिखाना चाहिए। सैफ अली खान (54) पर इलाहाबाद में एक घुसपैठिये ने चाकू से कई वार किए और फरार हो गया। थिकिस्सकों के मुताबिक सैफ अब खतरों से बहरा है। पटोले ने कहा कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता अभिनेता पर महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था 'ध्वस्त' होने का ज्वलंत उदाहरण है। कांग्रेस नेता ने कहा, "अगर मुंबई के बांद्रा जैसे व्यस्त इलाके में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो शहर में कौन सुरक्षित है? मुंबई, पुणे, बीड, परभणी और नागपुर में बढ़ती अपराध दर को देखते हुए, कोई भी आश्चर्य करता है कि क्या राज्य में प्रभावी कानून गृह मंत्री है भी या नहीं।" उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत 'महायुति' सरकार ने अराजकता को पनपने दिया है और खान पर हमला अपराधियों द्वारा भाजपा की कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती है। पटोले ने कहा कि भाजपा राज में अपराधी बेखोफ हो गए हैं। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेन्द्र फडणवीस तथा उनके पसंदीदा पुलिस महानिदेशक पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुए हैं।" उन्होंने कहा कि मुंबई में दो पुलिस आयुक्त होने के बावजूद, न तो राज्य में और न ही मुंबई में प्रभावी कानून और व्यवस्था है। उन्होंने दावा किया, "बीड में बढ़ता संगठित अपराध, अपराधियों को राजनीतिक समर्थन, परभणी में हिरासत में मौतें, बांद्रा में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर पर गोलीबारी गंभीर घटनाएं हैं। फडणवीस गृह मंत्री के तौर पर विफल रहे हैं। महाराष्ट्र में मशहूर हस्तियां, सत्ताधारी पार्टी के नेता और आम नागरिक सभी असुरक्षित हैं।" पटोले ने कहा, "अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी।" जैसे बयानों को दोहराने के बजाय, मुख्यमंत्री को कड़ी कार्रवाई करने का साहस जुटाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' की विशेष स्क्रीनिंग में फडणवीस के हिस्सा लेने का संदर्भ देते हुए दावा किया, "राज्य में अपराध दर बढ़ने से यह स्पष्ट है कि फडणवीस स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले के बाद, इस मुद्दे से निपटने के बजाय मुख्यमंत्री फिल्मों के प्रचार में व्यस्त हैं।" पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे ऐसा "निष्क्रिय" और "कमजोर" गृह मंत्री मिला है।



मुंबई, (भाषा) कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले ने महाराष्ट्र की 'ध्वस्त' हो चुकी कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है। पटोले ने कहा, "महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल के नेता और नागरिक असुरक्षित हैं। कांग्रेस नेता ने राज्य का गृह विभाग भी संभाल रहे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को 'अप्रभावी' और 'कमजोर' करार दिया और उनसे गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग की क्योंकि राज्य में बढ़ती अपराध दर सरकार की विफलता को दर्शाती है। पटोले ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को खोखले बयान देने के बजाय ठोस कार्रवाई करने का साहस दिखाना चाहिए। सैफ अली खान (54) पर इलाहाबाद में एक घुसपैठिये ने चाकू से कई वार किए और फरार हो गया। थिकिस्सकों के मुताबिक सैफ अब खतरों से बहरा है। पटोले ने कहा कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता अभिनेता पर महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था 'ध्वस्त' होने का ज्वलंत उदाहरण है। कांग्रेस नेता ने कहा, "अगर मुंबई के बांद्रा जैसे व्यस्त इलाके में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो शहर में कौन सुरक्षित है? मुंबई, पुणे, बीड, परभणी और नागपुर में बढ़ती अपराध दर को देखते हुए, कोई भी आश्चर्य करता है कि क्या राज्य में प्रभावी कानून गृह मंत्री है भी या नहीं।" उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत 'महायुति' सरकार ने अराजकता को पनपने दिया है और खान पर हमला अपराधियों द्वारा भाजपा की कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती है। पटोले ने कहा कि भाजपा राज में अपराधी बेखोफ हो गए हैं। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेन्द्र फडणवीस तथा उनके पसंदीदा पुलिस महानिदेशक पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुए हैं।" उन्होंने कहा कि मुंबई में दो पुलिस आयुक्त होने के बावजूद, न तो राज्य में और न ही मुंबई में प्रभावी कानून और व्यवस्था है। उन्होंने दावा किया, "बीड में बढ़ता संगठित अपराध, अपराधियों को राजनीतिक समर्थन, परभणी में हिरासत में मौतें, बांद्रा में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर पर गोलीबारी गंभीर घटनाएं हैं। फडणवीस गृह मंत्री के तौर पर विफल रहे हैं। महाराष्ट्र में मशहूर हस्तियां, सत्ताधारी पार्टी के नेता और आम नागरिक सभी असुरक्षित हैं।" पटोले ने कहा, "अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी।" जैसे बयानों को दोहराने के बजाय, मुख्यमंत्री को कड़ी कार्रवाई करने का साहस जुटाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' की विशेष स्क्रीनिंग में फडणवीस के हिस्सा लेने का संदर्भ देते हुए दावा किया, "राज्य में अपराध दर बढ़ने से यह स्पष्ट है कि फडणवीस स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले के बाद, इस मुद्दे से निपटने के बजाय मुख्यमंत्री फिल्मों के प्रचार में व्यस्त हैं।" पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे ऐसा "निष्क्रिय" और "कमजोर" गृह मंत्री मिला है।

## रोहित ने संकेत दिया, खिलाड़ियों को 10 सूत्री निदेश पर कुछ संदेह, बीसीसीआई से मुद्दे पर चर्चा करेंगे



**मुंबई, (भाषा)** मुख्य कोच गौतम गंभीर की सलाह पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा तैयार किए गए 10 सूत्री अनुशासनात्मक दिशा-निर्देशों में कुछ नियमों पर रोहित शर्मा को असमजस है और भारतीय कप्तान इस मुद्दे पर बोर्ड सचिव देवाजीत सैकिया से चर्चा करने वाले हैं। बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर दिशा-निर्देशों की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया की खबरों में ये 10 सूत्री निदेश सामने आ चुके हैं। नीति दस्तावेज में एक मुख्य विवाद पुराने दिनों की ओर लौटना है जब परिवारों को लंबे दौरों पर केवल 14 दिन के लिए अनुमति दी जाती थी। किसी भी बदलाव के लिए कोच गंभीर की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह समझा जाता है कि यह नियम टीम के खिलाड़ियों को अच्छा नहीं लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले जब रोहित चयनकर्ताओं के अध्यक्ष अजीत अगरकर के पास बैठे थे तो उन्हें मुंबई के अपने पूर्व साथी से यह कहते हुए सुना गया, “अब मेरे को बैठना पड़ेगा सचिव के साथ। फेमिली-वैमिली का डिस्कस करने के लिए, सब मेरे को बोल रहे हैं या फिर। हर कोई (खिलाड़ी) मुझसे पूछ रहा है।” रोहित की टिप्पणी मीडिया के लिए नहीं थी लेकिन यह ‘माइक्रोफोन’ में रिकॉर्ड हो गई जिसका मतलब समझना मुश्किल नहीं था। जब रोहित ने दिशा-निर्देशों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, “आपको इन नियमों के बारे में किसने बताया? क्या यह बीसीसीआई के आधिकारिक हैंडल से आया है? इसे आधिकारिक तौर पर आने दें।” हालांकि जब अगरकर ने बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) मसौदा तैयार किया गया है। अगरकर से पूछा गया कि आखिर क्या गलत हुआ कि टी20 विश्व कप जीतने के छह महीने के अंदर बीसीसीआई को उन्हीं खिलाड़ियों के साथ एक यात्रा नीति दस्तावेज की आवश्यकता पड़ गई? ऑस्ट्रेलिया की हार पर चर्चा करने वाली समीक्षा समिति की बैठक का हिस्सा रहे अगरकर ने कहा, “अगर हम इस पर बात करते रहेंगे तो शायद यह चर्चा जारी रहेगी।” उन्होंने तर्क देने की कोशिश करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि हर टीम के कुछ नियम होते हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में कई चीजों के बारे में बात की है जिसमें आप एक टीम के रूप में सुधार कर सकते हैं। यह कोई स्कूल नहीं है। यह कोई सजा नहीं है। अगरकर ने कहा, “बस इतना है कि आपको पास कुछ नियम होते हैं और जब आप राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं तो आप उन नियमों का पालन करते हैं। ये परिपक्व खिलाड़ी हैं। वे अंतरराष्ट्रीय खेल में अपने आप में सुपरस्टार हैं।” कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि ये नियम हमेशा से ही रहे हैं और अगरकर ने उन्हें ‘प्रोटोकॉल’ कहा है जिसका राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करते समय पालन करना होता है। उन्होंने कहा, “लेकिन आखिरकार आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आप स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं जैसा कि हर टीम करती है। मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से नियम लागू हैं।” अगरकर ने कहा, “हो सकता है कि हमने इस बारे में अभी बात की हो और इसे सामने रखा हो, लेकिन उनमें से बहुत से पहले ही लागू हो चुके हैं। अंत में टीम के अनुकूल क्या है, उसी के अनुसार आप इन्हें सुधारते रहते हैं। मैं यहां बैठकर यह चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ कि हर मैच के पीछे क्या रणनीति होती है लेकिन यह मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट है।” रोहित ने कहा, “गौतम गंभीर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैदान पर उतरने के बाद कप्तान के मैदान पर किए जा रहे काम पर भरोसा करते हैं।”

## चार स्पिनरों के जांचे परखे फार्मूले पर निर्भरता के कारण चैम्पियंस ट्रॉफी से सिराज बाहर

**मुंबई, (भाषा)** स्पिन पर भारत की निर्भरता और पुरानी गेंद से मोहम्मद सिराज के प्रभावित नहीं कर पाने के कारण चैम्पियंस ट्रॉफी टीम से उन्हें बाहर रहना पड़ गया। भारत ने 19 फरवरी से शुरू हो रहे आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिये 15 सदस्यीय टीम का शनिवार को ऐलान किया। भारत को अपने सारे मैच दुबई में खेलने हैं। दुबई की पिचे तेज गेंदबाजों की ज्यादा मदद नहीं करती लिहाजा भारत ने वेस्टइंडीज में हुए टी20 विश्व कप की तरह चार स्पिनरों कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंग्टन सुंदर को चुना है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वानखेडे स्टेडियम पर टीम का ऐलान करने के बाद मीडिया से कहा, “ हम ऐसी टीम चाहते थे जिसमें हमारे पास दोनों विकल्प हों यानी नयी गेंद से गेंदबाजी का और डैथ ओवरों का भी।” जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो वनडे के लिये उपलब्ध नहीं हैं और 12 फरवरी को अहमदाबाद में आखिरी मैच में ही लौटेंगे। नागपुर और कटक में पहले दो वनडे के लिये हर्षित राणा को चुना गया है। रोहित ने स्वीकार किया कि सिराज की गैर मौजूदगी में टीम में अनुभव की कमी लग रही है लेकिन उन्होंने इस फैसले का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, “ हम चाहते थे कि अर्शदीप सिंह आंसरी में और मोहम्मद शमी नयी गेंद से गेंदबाजी करे। अगर सिराज नयी गेंद से गेंदबाजी नहीं कर रहा है तो वह इतना प्रभावित नहीं कर पाता।” उन्होंने कहा, “ हमने इस पर विस्तार से बात की और हम तीन तेज गेंदबाजों को ही लेकर जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे हरफनमौला उपलब्ध हों। सिराज के लिये यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमें विशेष भूमिका के लिये विशेष खिलाड़ी चाहिये।”

## इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे बुमराह, उन्हें आराम करने को कहा गया: अगरकर



**मुंबई, (भाषा)** मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने शनिवार को कहा कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो वनडे के लिए फिट नहीं हो पाएंगे जिसके कारण हर्षित राणा को उनकी जगह शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे मुख्य तेज गेंदबाज की स्थिति पर मेडिकल टीम से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। बुमराह को हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच की श्रृंखला के बाद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगरकर ने कहा, “बुमराह को पांच सप्ताह के लिए आराम करने को कहा गया है जिससे वह इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो वनडे के लिए उपलब्ध नहीं हो पायेंगे। हम उनकी फिटनेस का इंतजार कर रहे हैं और हमें मेडिकल टीम से उनकी स्थिति के बारे में फरवरी की शुरुआत में पता चलेगा।” बुमराह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के अंत में चोटिल हो गए थे और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सिडनी में अंतिम टेस्ट की दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर पाये थे जिसके बाद उनका रकून किया गया था। अगरकर ने कहा, “उनकी फिटनेस के बारे में हमें शायद अगले हफ्ते या उससे ज्यादा समय में उनकी फिटनेस के बारे में और जानकारी मिलेगी। बेहतर होता अगर बीसीसीआई इसके बारे में अपडेट करे। मैं जो बताऊँ, हो सकता है वह सही नहीं हो। मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें पांच हफ्ते के लिए गेंदबाजी से दूर रहने के लिए कहा गया था जो फरवरी के पहले हफ्ते की शुरुआत है।” उन्होंने कहा, “हमें शायद उस समय तक थोड़ा और पता चलेगा। मुझे यकीन है कि बीसीसीआई फिजियो से कुछ कह सकता है।” ब्रिसबेन टेस्ट में भारत की हार के बाद कप्तान रोहित ने पिछले महीने मोहम्मद शमी की फिटनेस स्थिति पर बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) से जयवा मांगा था। शनिवार को अगरकर ने भी यही बात कही।

# ओलंपिक पदक की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए: मनु भाकर

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने कहा कि एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक पदक से बड़ा कोई स्मृति चिन्ह नहीं है। इसलिये इसकी गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए। पेरिस ओलंपिक के पदकों की चमक इन्हें दिए जाने के कुछ ही महीनों बाद फीकी पड़ गई है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर मिश्रित



टीम स्पर्धा में भाकर द्वारा जीते गए दो कांस्य पदकों की चमकीली ऊपरी परत उखड़ गई जिससे उनका अंदर का हिस्सा दिख रहा है। उन्होंने और दुनिया भर के कई खिलाड़ियों ने पदक की चमक फीकी होने के मुद्दे को उठाया और उन्हें बदलने की मांग की। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजे जाने के बाद 22 वर्षीय इस शीर्ष निशानेबाज ने पुष्टि की कि उनके पदकों की चमक फीकी पड़ गई थी। खेल रत्न प्राप्त करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भाकर ने कहा, “पदक मिलने के तुरंत बाद दो तीन दिन के अंदर ही चमक फीकी होनी शुरू हो गई। मैं यह अपने पदक को देखने के बाद कह सकती हूँ। ओलंपिक पदक जीवन भर संजोकर रखने वाली चीज है क्योंकि उस पदक के साथ बहुत बड़ी याद जुड़ी होती है।” उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि किसी एथलीट के करियर में इससे बड़ी कोई यादगार चीज नहीं हो सकती। इसकी गुणवत्ता शीर्ष स्तर की होनी चाहिए और अगर आईओसी (अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति) इसे बदल रही है तो यह बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि भारत और अन्य देशों के बहुत से खिलाड़ियों ने शिकायत की है।” आईओसी ने कहा कि फीके हुए पदकों को ‘मोनेई डे पेरिस (फ्रांस का राष्ट्रीय टकसाल)’ द्वारा व्यवस्थित रूप से बदला जाएगा। खिलाड़ियों को मिलने वाला नया पदक पुराने के समान ही होगा। भाकर ने पेरिस में अपनी सफलता के बाद प्रतियोगिताओं से ब्रेक ले लिया था, उन्होंने साल के अंत में होने वाले विश्व कप फाइनल और राष्ट्रीय चैंपियनशिप को छोड़ दिया था, लेकिन 2028 लॉस एंजिल्स खेलों को ध्यान में रखते हुए वह पिछले कुछ महीनों से ट्रेनिंग कर रही हैं। उन्होंने कहा, “हां मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, ढाई महीने हो गए हैं। 2028 ओलंपिक की दौड़ तक उतार-चढ़ाव तो चलेगा।

## छेत्री के गोल से बेंगलुरु एफसी को मिला एक अंक, केरला ब्लास्टर्स ने खेला गोलरहित ड्रॉ

**हैदराबाद, (भाषा)** महान फुटबॉलर सुनील छेत्री के सत्र के 10वें गोल की मदद से बेंगलुरु एफसी ने शनिवार को यहां इंडियन सुपर लीग मैच में हैदराबाद एफसी से 1–1 ड्रॉ खेलकर अंक बांटे। देवेंद्र मुग्गावकर ने पहले हाफ में 21वें मिनट में गोल कर हैदराबाद एफसी को 1–0 से आगे कर दिया। लेकिन 40 साल के छेत्री ने 78वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया। इस तरह छेत्री अपने आईएसएल करियर में दूसरी दफा 10 से ज्यादा गोल करने में कामयाब रहे। उन्होंने 2017–18 अभियान में 14 गोल किये थे। कोच्चि में एक अन्य मैच में केरला ब्लास्टर्स ने नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी से गोलरहित ड्रॉ खेलकर अंक बांटे।

### रेल सघां ने आठवें वेतन आयोग के गठन के फैसले का स्वागत किया

**नयी दिल्ली, (भाषा)** अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (एआईआरएफ) ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग के गठन का केंद्र सरकार का फैसला उसके कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, “यह विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान की हमारी सामूहिक मान्यता को दर्शाता है।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। मिश्रा ने एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ भारत सरकार को इस लंबे समय से लंबित मांग पर विचार करने के लिए धन्यवाद दिया। मिश्रा ने उम्मीद जताई कि आयोग समय-समया के भीतर अपना काम पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय “हमारे देश की सेवा करने वाले समर्पित कर्मचारियों के लिए उचित और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने के हमारे चल रहे प्रयासों” में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

## अंकिता ने नैखटा के साथ 2025 सत्र का पहला युगल खिताब जीता

**नयी दिल्ली, (भाषा)** भारत की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैाना ने शनिवार को यहां ब्रिटिश जोड़ीदार नैखटा बैस के साथ आईटीएफ डब्ल्यू50 स्पर्धा की चैम्पियन बनने के साथ ही नौ महीने में अपना पहला युगल खिताब जीता। गैर वरीयता प्राप्त भारतीय-ब्रिटिश जोड़ी ने डीएलटीए परिसर में हुए फाइनल मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसी एनी और जेसिका फेला की जोड़ी को एक घंटे 42 मिनट तक चले मैच में 6–4, 3–6, 10–8 से हराया। अंकिता एकल स्पर्धा के पहले दौर में ही बाहर हो गई थीं लेकिन उन्होंने युगल खिताब जीतकर इस निराशा की भरपाई की। अंकिता ने इससे पहले अप्रैल 2024 में जापान में काशीवा में अपनी पहली युगल ट्रॉफी जीती थी। उन्होंने तब ताइपे की चिया यी त्साओ के साथ जोड़ी बनाई थी। इस बीच सातवीं वरीयता प्राप्त तातियाना प्रोजोरोवा और दूसरी वरीयता प्राप्त पन्ना उडवार्डी ने अपने-अपने मैचों में जीत के साथ फाइनल में जगह बनायीं। दिन के पहले सेमीफाइनल में हंगरी की उडवार्डी ने ब्रिटिश चौथी वरीयता प्राप्त युरिको लिली मियाजाकी को 6–3, 6–2 से शिकस्त दी जबकि तातियाना ने लातविया की शीर्ष वरीयता प्राप्त दार्जा सेमेनिस्ट्जाको 7–5, 6–2 से मात दी।

## हैदराबाद तूफान्स ने तमिलनाडु ड्रैगन्स को 4–0 से हराया

**रांची,** गोंजालो पेलाट के दो गोल से हैदराबाद तूफान्स ने शनिवार को यहां पुरुष हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) में तमिलनाडु ड्रैगन्स को 4–0 से हराकर अपना अग्रिम अभियान जारी रखा। पेलाट ने 21वें और 48वें मिनट में दो गोल किये जबकि आर्थर डि स्क्रूवेर ने 31वें और टिम ब्रांड ने 33वें मिनट में गोल किया। इस जीत की बदौलत हैदराबाद तूफान्स सात मैच में 13 अंक लेकर दूसरे स्थन पर पहुंच गया है और तमिलनाडु ड्रैगन्स से पीछे है जो 15 अंक लेकर शीर्ष पर कायम है।

## पहले टी20 मैच के लिये भारत और इंग्लैंड की टीमों कोलकाता पहुंची

**कोलकाता, (भाषा)** विश्व चैम्पियन भारतीय टीम और यहां दौरै पर आई इंग्लैंड टीम बुधवार को होने वाले पहले टी20 मैच के लिये यहां पहुंच गईं। ऐतिहासिक इंडन गार्ड्स पर तीन साल बाद पहला टी20 मैच हो रहा है। दोनों टीमों के बीच पांच टी20 और तीन वनडे मैचों की श्रृंखला खेली जायेगी। एसए 20 खेलकर आये इंग्लैंड के हरफनमौला लियाम लिविंग्स्टान सबसे पहले पहुंचे जो दक्षिण अफ्रीका से सीधे आये थे। जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम के बाकी सदस्य दुबई से शाम को यहां पहुंचे। टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने अपने शहरों से आये हैं। नीतिश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह 4 . 30 पर पहुंचे। उसके बाद कप्तान सुर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा आये। मुख्य कोच गौतम गंभीर और बाकी खिलाड़ी शाम को पहुंचे। करीब चौदह महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे मोहम्मद शमी और हरफनमौला हार्दिक पंड्या देर रात को पहुंचेंगे। दोनों टीमें पहले मैच से पूर्व तीन अभ्यास सत्रों में भाग लेंगी। दूसरा टी20 चेन्नई में 25 जनवरी को और तीसरा दो फरवरी को मुंबई में खेला जायेगा।

## गत चैम्पियन सिनर, रुने, स्वियातेक और मॉफिल्स ऑस्ट्रेलियाई ओपन के चौथे दौर में

**मेलबर्न, (एपी)** गत चैंपियन यानिक सिनर ने शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अमेरिका के 46वीं रैंकिंग वाले मार्कोस गिरोन को 6–3, 6–4, 6–2 से हराकर चौथे दौर में अपनी जगह पक्की की। विश्व की दूसरे नंबर की महिला खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने बेहतरीन खेल का नजारा पेश करते हुए ब्रिटेन की एम्मा राडुकानु पर आसान जीत दर्ज की जबकि गएल मॉफिल्स ने 38 साल की उम्र में भी अपना दमदार खेल दिखाते चौथे दौर में जगह बनाई। सिनर की यह लगातार 17वीं जीत है। इटली के 23 साल के खिलाड़ी ने चौथी बार इस ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में जगह बनाई है। उनके सामने विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर काबिज होल्गर रुने की चुनौती होगी। डेनमार्क के रुने ने मियोमिर केकमानोविच को पांच सेट तक चले मुकाबले में 6–7, 6–3, 4–6, 6–4, 6–4 से शिकस्त दी। स्वियातेक ने मैच के अंतिम 11 गेम जीतकर अमेरिकी ओपन में 2021 की चैंपियन राडुकानु को 6–1, 6–0 से हराया। पिछले साल डोमिंग माम्ले के कारण एक महीने का निलंबन स्वीकार करने वाली स्वियातेक ने चार बार फ्रेंच ओपन ओर 2022 में अमेरिकी ओपन का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में हालांकि वह अभी तक सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई है। स्वियातेक ने मैच के बाद कहा, “मैंने अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इसे बर्‍या करने के लिए अभी मेरे पास बहुत शब्द नहीं हैं।” मिशेलसन अगले दौर में ऑस्ट्रेलिया के आठवीं वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनाउर का सामना करेंगे जिन्होंने 31वें वरीय फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को 5–7, 7–6 (3), 6–3, 6–3 से हराया। पिछले साल अमेरिकी ओपन के उपविजेता और यहां चौथी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज बाहर हो गए हैं। उन्हें 38 वर्षीय गेल मॉफिल्स ने 3–6, 7–5, 7–6 (1), 6–4 से हराया। मॉफिल्स साल के पहले ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में पहुंचने वाले 38 साल या इससे अधिक उम्र के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस तरह से रोजर फेडरर की बराबरी की। स्वयातेक अंदर दौर में जर्मनी की 128वीं रैंकिंग वाली ईवा लिस का सामना करेगी।

## अंडर–19 महिला टी20 विश्व कप: बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की



**कुआलालंपुर, (भाषा)** बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को आईसीसी अंडर–19 महिला टी20 विश्व कप के बारिश से प्रभावित शुरुआती दिन जीत हासिल की। दक्षिण अफ्रीका ने अहम मैच में न्यूजीलैंड को हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया जबकि बांग्लादेश ने कम स्कोर वाले मैच में नेपाल को पांच विकेट से हराया। काओइम्हें ब्रे ने सिर्फ एक रन खर्च कर तीन विकेट झटकें जिससे ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को आसानी से हराया। मलेशिया में खराब मौसम के कारण तीन मैच रद्द कर दिए गए। इंग्लैंड और आयरलैंड का मुकाबले में और सात गेंद का खेल हुआ होता तो मैच का परिणाम निकल जाता। टूर्नामेंट में पदार्पण कर रहे नाइजीरिया और समोआ तथा अमेरिका और पाकिस्तान का मैच खराब मौसम के कारण शुरू नहीं हो सका। बांग्लादेश ने ग्रुप डी के मैच में नेपाल को 18.2 ओवर में 52 रन पर आउट करने के बाद 13.2 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। नेपाल के लिए सना परवीन ने 32 गेंद में सबसे ज्यादा 19 रन बनाये जबकि सीमान केसी (10) दोहरे अंक में रन बनाने वाली टीम की सिर्फ दूसरी बल्लेबाज रही। नेपाल के पांच बल्लेबाज रन आउट हुए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने भी 11 रन तक तीन विकेट गंवा दिये थे लेकिन सादिया इस्माम (16) और कप्तान सुमेया अख्तर (12) ने विकेटों के पतन को रोककर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका ने बारिश से प्रभावित ग्रुप सी के 11 ओवर के मैच में न्यूजीलैंड पर 22 रन की जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज जेमिमा बोथा (24 गेंद में 32 रन) और सिमोन लुरेंस (14 गेंद में 21 रन) के साथ कराबो मेसो (14 गेंद में 25 रन) के उपयोगी योगदान से टीम ने सात विकेट पर 91 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड को पांच विकेट पर 69 रन पर रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 15 साल की ब्रे की शानदार गेंदबाजी से ग्रुप डी के मैच में स्कॉटलैंड को 48 रन पर आउट करने के बाद 6.4 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। ब्रे ने 3.1 ओवर में एक रन खर्च कर तीन विकेट चटकाये। स्कॉटलैंड के लिए एम्मा वालसिघम ने सबसे ज्यादा 12 रन बनाये। इंग्लैंड ने ग्रुप बी के मैच में आयरलैंड के खिलाफ सात विकेट पर 144 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। आयरलैंड की पारी के चौथे ओवर में बारिश के खलल के कारण मैच रद्द हो गया। बारिश के खलल से पहले आयरलैंड ने 3.5 ओवर में दो विकेट पर 28 रन बना लिये थे। टी20 में परिणाम के लिए दूसरी पारी में पांच ओवर का खेल जरूरी है ऐसे में महज सात गेंद के कारण इस मैच का परिणाम नहीं निकल सका।

## स्मरण के शतक ने शोरे से प्रयास पर पानी फेरा, कर्नाटक ने पांचवी बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी



**वडोदरा, (भाषा)** ध्रुव शोरे ने लगातार तीसरा शतक जड़ा लेकिन कर्नाटक ने स्मरण रविचंद्रन की कलात्मक शतकीय पारी की मदद से शनिवार को यहां एक बड़े स्कोर वाले फाइनल में विदमं को 36 रनों से हराकर पांचवीं बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। कर्नाटक की टीम पांचवीं बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी। टीम हर बार खिताबी मुकाबले को जीतने में सफल रही है। वामहस्त बल्लेबाज स्मरण की 92 गेंद में 101 की पारी खेलने के अलावा चौथे विकेट के लिए के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज कृष्णन श्रीजीत (74 गेंद में 78 रन) के साथ 160 और पांचवें विकेट के लिए अभिनव मनोहर (42 गेंद में 79 रन) के साथ 106 की आक्रामक साझेदारी कर कर्नाटक को 50 ओवर में छह विकेट पर 348 रन तक पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए शोरे की 110 और आखिरी ओवरों में हर्ष दुबे की 30 गेंद में 63 रन की पारी के बावजूद कर्नाटक की टीम 48.2 ओवर में 312 रन पर आउट हो गयी। हर्ष ने पांच चौके और इतने ही छक्के लगाये और आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में शतक लगाने वाले शोरे को दूसरे छोर से फाइनल साथ नहीं मिला। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ करुण नायर (27) के आउट होने के बाद विदमं का मध्यक्रम दबाव में आ गया। विदमं की टीम बिना कोई मैच गंवाए फाइनल में पहुंची थी और टूर्नामेंट में उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की बड़ी परियों के कारण मध्यक्रम को बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिल सका था। फाइनल के दबाव में उसकी बल्लेबाजी बिखर गयी। भारत के वनडे टीम में जगह के लिए करुण के नाम पर चयनकर्ताओं के बीच गंभीर चर्चा हुई थी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 389.5 की औसत से 779 रन बनाये। शोरे ने एक छोर से कुछ शानदार चौके लगाते हुए नायर के साथ 56 और अनुभवी जितेश शर्मा (34) के साथ 62 रन की साझेदारी की। विदमं की टीम हालांकि बीच के ओवरों में ज्यादा बाउंड्री नहीं लगा सकी जिससे दबाव बढ़ता गया। कर्नाटक के मध्यम गति के गेंदबाज वासुकी कौशिक ने इस बड़े स्कोर वाले मैच में 10 ओवर में 47 रन पर तीन विकेट झटक कर प्रभावित किया। अमितान शंडी ने 9.2 ओवर में 58 रन देकर तीन विकेट लिये। जबकि प्रसिद्ध ने भी तीन विकेट लिये लेकिन उन्होंने 10 ओवर में 84 रन लुटाये। शोरे को भारतीय टीम के इस गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्होंने प्रसिद्ध खिलाफ छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। शोरे ने अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाये। इससे पहले स्मरण ने ऑफ साइड में कुछ आकर्षक शाॅट खेल कर प्रभावित किया। मनोहर ने क्रीज पर आते ही बाउंड्री की छड़ी लगा दी। उन्होंने 42 गेंद की पारी में 10 चौके और चार छक्के के साथ टीम को 350 रन के करीब पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

<sup>[1]</sup> मुंबई, (भाषा) मुख्य कोच गौतम गंभीर की सलाह पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा तैयार किए गए 10 सूत्री अनुशासनात्मक दिशा-निर्देशों में कुछ नियमों पर रोहित शर्मा को असमजस है और भारतीय कप्तान इस मुद्दे पर बोर्ड सचिव देवाजीत सैकिया से चर्चा करने वाले हैं

<sup>[2]</sup> मुंबई, (भाषा) मुख्य कोच गौतम गंभीर की सलाह पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा तैयार किए गए 10 सूत्री अनुशासनात्मक दिशा-निर्देशों में कुछ नियमों पर रोहित शर्मा को असमजस है और भारतीय कप्तान इस मुद्दे पर बोर्ड सचिव देवाजीत सैकिया से चर्चा करने वाले हैं

## दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर ड्रोन और अन्य 'हवाई प्लेटफार्म' के संचालन पर प्रतिबंध



नयी दिल्ली. (भाषा) गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 'उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्म' के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 18 जनवरी से लागू होगा और एक फरवरी तक जारी रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि भारत विरोधी आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी ऐसे हवाई 'प्लेटफार्म' का उपयोग करके सार्वजनिक सुरक्षा, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। आदेश में कहा गया, "दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर 'उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्म' की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।"

**झारखंड में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिये 'शिशु शक्ति' खाद्य पैकेट का वितरण शुरू रांची, (भाषा)** झारखंड सरकार ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 'शिशु शक्ति' खाद्य पैकेट का वितरण शनिवार से शुरू कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि शिशु शक्ति नामक खाद्य पैकेट, सरकार द्वारा वर्तमान में उपलब्ध कराए जा रहे राशन की तुलना में ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है। अधिकारी के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य राज्य को कुपोषण मुक्त बनाना है। राज्य सरकार में मंत्री दीपक बिश्नो और सिंहभूम की सांसद जोबा माझी ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड में पायलट परियोजना के तौर पर इस पहल की शुरुआत की है।

## एयरो इंडिया शो: बीबीएमपी ने 23 जनवरी से 17 फरवरी तक मांस दुकानों, मांसाहारी भोजनालयों पर पाबंदी लगाई

बंगलुरु, (भाषा) बृहत बंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर 23 जनवरी से 17 फरवरी तक येलहंका वायुसेना स्टेशन के 13 किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकानों और मांसाहारी भोजनालयों को बंद करने का आदेश दिया है। बीबीएमपी ने कहा कि यह कदम 10 से 14 फरवरी तक होने वाले एयरो इंडिया शो के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है। बीबीएमपी सूत्रों ने बताया कि यह कदम मुख्य रूप से अत्यास सत्र और कार्यक्रम के दौरान विमानों से पक्षियों के टकराने को रोकने के लिए उठाया गया है। येलहंका जॉन के संयुक्त आयुक्त कार्यालय द्वारा 17 जनवरी को जारी किये गए नोटिस के अनुसार, निर्दिष्ट क्षेत्र में मांस से संबंधित सभी प्रतिष्ठान 23 जनवरी से 17 फरवरी तक बंद रहेंगे। इसमें इस अवधि के दौरान मांसाहारी व्यंजन परोसने या बेचने पर प्रतिबंध शामिल है। बीबीएमपी ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर बीबीएमपी अधिनियम 2020 और भारतीय विमान नियम 1937, नियम 91 के तहत दंड लगाया जाएगा। एयरो इंडिया 2025, एक द्विदिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें अत्याधुनिक एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ सैन्य और अन्य विमानों की एक विविध श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाएगा।



## मुक्त विश्वविद्यालय ने महाकुंभ अध्ययन के लिए प्रवेश शुरू किया

महाकुंभ नगर, (भाषा) उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने महाकुंभ अध्ययन के लिए छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने मेला क्षेत्र में अनंत माधव मार्ग सेक्टर-सात स्थित दूरस्थ शिक्षा जागरूकता शिविर में शनिवार को इस पाठ्यक्रम की शुरुआत की। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ प्रभात मिश्रा ने बताया कि शनिवार को महाकुंभ में दूरस्थ शिक्षा की प्रासंगिकता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने महाकुंभ क्षेत्र में कुंभ अध्ययन में प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रचार अभियान चलाया जाएगा। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के पूर्व निदेशक एस सी मिश्र इस प्रमाण पत्र कार्यक्रम के पहले विद्यार्थी बने। मिश्रा ने बताया कि शिविर में ही 100 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय ने पहली बार कुंभ अध्ययन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें महाकुंभ से संबंधित सभी जानकारीयों समाहित की गई हैं। महाकुंभ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को इसमें प्रवेश लेना चाहिए जिससे उन्हें कुंभ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया का ध्यान प्रयागराज के महाकुंभ पर है। ऐसे में मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए उन सभी के लिए छह महीने का यह प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसमें कुंभ के आयोजन से लेकर सभी तथ्यों को समाहित किया है। कुलपति ने बताया कि इसका अध्ययन पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय की तरफ से एक विशिष्ट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र कार्यक्रम से संबंधित जानकारी महाकुंभ में सभी सेक्टर में श्रद्धालुओं को कुंभ गाइड के माध्यम से पर्व वितरित करके दी जाएगी।



## हरित महाकुंभ के संकल्प की आवश्यकता



तीर्थ , व्रत और पर्व- उत्सव हमें आत्ममंथन और सुधार-परिष्कार का संदेश देते हैं। भिन्न-भिन्न रूपों में प्लास्टिक जीवन के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण को भी कुपूर कर रहा है। इससे जल एवं खाद्य पदार्थ भी तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं। क्या इस महाकुंभ के अवसर पर हम हरित महाकुंभ का संकल्प ले सकते हैं? 144 वर्ष के बाद महायोग के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। गिगत 2-3 दिन में ही करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। छोटे बड़े सैकड़ों अखाड़े, लाखों संत और करोड़ों भक्त यह भव्य और दिव्य समारोह में। इस बार के महाकुंभ में लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने का अनुमान है जिसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज कुंभ इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है कि वहां गंगा,यमुना और सरस्वती का प्रयाग अथवा संगम है। क्या हमने इन पवित्र नदियों को प्रदूषित नहीं किया है? अशोधित सीवरेंज,घरेलू कूड़ा एवं प्लास्टिक सीधे नदियों में बह रही है। क्या हम ऐसे प्रदूषित जल में स्नान कर पाएंगे? तीर्थ नगरी प्रयागराज सभी का खुले मन से स्वागत तो करती ही है, वह जन-जन को- सब समान, सबका सम्मान का भी संदेश देती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आदि ग्रंथ वेदों से लेकर आज तक जल और जल स्रोतों विशेष रूप से नदियों के संरक्षण-संवर्धन के लिए विशेष चिंता एवं चिंतन मिलता है। नदियों पर अथवा कुंभ जैसे अससों पर स्नान के माध्यम से यह संदेश भी निहित है कि हम जल स्रोतों अथवा नदियों को स्वच्छ रखें, उनका संरक्षण- संवर्धन करें। मां गंगा की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व के कारण ही कहा गया है- गंगे तव दर्शनात् मुक्ति अर्थात् मां गंगा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। फिर महाकुंभ में तो लाखों आध्यात्मिक विभूतियां एक साथ साधना एवं गंगा स्नान में लीन रहती हैं। इसलिए वहां स्नान करने वाले सामान्य व्यक्ति को भी पुण्य लाभ मिलता है।

हाल ही में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिंतानंद सरस्वती ने सभी को कुंभ का संदेश देते हुए यह कहा कि- हमारे मंदिर, धाम, तीर्थ,संत परंपरा और हमारी सनातन संस्कृति प्रकृति-पर्यावरण और श्रेष्ठ परम्पराओं के संरक्षण-संवर्धन का संदेश देते हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि- आस्था है तो अस्तित्व है, कुंभ श्रद्धा और आस्था की कड़ियों को जोड़ता है, यह भारतवर्ष के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कुंभ को दंगगी मुक्त, प्लास्टिक मुक्त एवं भाईचारे से युक्त बनाने का आवाह किया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्लास्टिक बहुत तेजी से प्रवेश कर रहा है। दैनिक जीवन के छोटे-छोटे कार्यों और आवश्यकताओं में भी प्लास्टिक से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की बीमारियां और स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। महाकुंभ श्रद्धा, आस्था और अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र है। अनुमान के अनुसार इस बार कुंभ में लगभग 60 से 60 लाख टन कूड़े एवं प्लास्टिक आदि कचरे की संभावना है। कई संतों एवं संस्थाओं ने हरित कुंभ का आवाह किया है। उनका कहना है कि जब आप कुंभ में आएंगे तो प्लास्टिक की बोतल अथवा थालियां साथ लेकर न आएंगे। उन्होंने स्वर्गन दिया है- अपनी थाली, अपना थैला। खाने के लिए घर से अपनी स्टील या पीतल की थाली लेकर आए। अपना सामान और थाली आदि रखने के लिए कपड़े के थैले का प्रयोग करें,प्लास्टिक की थालियों के प्रयोग से बचें। यह हमारी सामान्य आदत में आ चुका है कि हम प्लास्टिक की थालियों में,प्लास्टिक की चम्मच से खाना खाकर उन्हें यहां वहां फेंक देते हैं, थैलियों का प्रयोग भी बहुत अधिक बढ़ा है, यदि हम वहां प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और कूड़ा छोड़ेंगे तो पवित्र कुंभ और नदी के किनारे प्रदूषित हो जाएंगे। हमारे बाद जाने वाले श्रद्धालु फिर साफ और स्वच्छ वातावरण एवं जल में स्नान किस प्रकार कर पाएंगे? ध्यान रहे कुंभ केवल सागर मंथन ही नहीं है अपितु यह आत्ममंथन की भी यात्रा है। आज के नए भारत को प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेना ही होगा, क्योंकि प्रकृति बचेगी तो संस्कृति बचेगी,हमारी संतति बचेगी और हमारा भविष्य बचेगा। इसलिए आइए हरित कुंभ- प्लास्टिक मुक्त जीवन और हरित जीवन का संकल्प लें।

## महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री नियुक्त, धनंजय मुंडे को सूची में जगह नहीं मिली

मुंबई, (भाषा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एवं महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को शनिवार को राज्य सरकार द्वारा जारी प्रभारी मंत्रियों की सूची में जगह नहीं मिली। महाराष्ट्र में मंत्रियों को एक या उससे अधिक जिलों की जिम्मेदारी दी जाती है। पिछले महीने राज्य में भाजपा-राकांपा-शिवसेना की नयी सरकार के गठन के बाद से ही इस घोषणा का इंतजार था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (जो गृह विभाग भी संभाल रहे हैं) नक्सल प्रभावित गढ़चिरोली जिले के प्रभारी मंत्री होंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार को उनके गृह जिले पुणे के अलावा बीड जिले की जिम्मेदारी भी दी गयी है। बीड के परली से विधायक धनंजय मुंडे पिछले महीने राज्य सरकार के दौरान मध्य महाराष्ट्र के बीड जिले के संरक्षक मंत्री थे। हालांकि हाल ही में जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर वह विपक्ष और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों के निशाने पर आ गए। इस मामले में मुंडे के सहयोगी वाल्मिक करराड को गिरफ्तार किया गया है। राकांपा प्रमुख अजित पवार ने इस विवाद को लेकर मुंडे से इत्तीका मांगने से इनकार कर दिया था। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे (राज्य के उपमुख्यमंत्री) मुंबई शहर के साथ-साथ ठाणे जिले के भी प्रभारी मंत्री होंगे। इस बीच मुंडे ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में अजित पवार को बधाई दी। मुंडे ने कहा कि उन्होंने पवार से बीड जिले में "बदली हुई राजनीतिक और सामाजिक स्थिति" के मद्देनजर बीड का प्रभारी मंत्री बनने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि पवार के बीड का प्रभारी मंत्री बनने से वहां पुणे की तरह विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुंडे के अलावा, कैबिनेट मंत्री दादाजी भुसे, दत्ता भरणे, भरत गोगावले और राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक और योगेश कदम को भी कोई जिला आवंटित नहीं किया गया। प्रदेश भाजपा प्रमुख चन्द्रशेखर बावनकुले को नागपुर और अमरावती का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।

## भारत-बांग्लादेश सीमा पर किसानों की झड़प का मामला सुलझा, स्थिति नियंत्रण में : बीएसएफ

मालदा(प.बंगाल), (भाषा) भारत-बांग्लादेश सीमा पर शनिवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सीमा चौकी के नजदीक दोनों देशों के किसानों के बीच कहासुनी के बाद हुई संक्षिप्त झड़प की वजह से तनाव पैदा हो गया। केंद्रीय अर्धसैनिक बल ने यह जानकारी दी। बल ने एक बयान में कहा कि बीएसएफ और उसके बांग्लादेशी समकक्ष बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने तत्काल हस्तक्षेप किया और जल्द ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया। बीएसएफ के मुताबिक यह घटना पूर्वाह्न करीब 11:45 बजे हुई जब अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास काम कर रहे भारतीय किसानों ने बांग्लादेशी किसानों पर फसल चोरी करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि कहासुनी ने जल्द ही उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के किसान बड़ी संख्या में एकत्र हो गए, एक-दूसरे को गालियां देने लगे और एक-दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। बीएसएफ ने एक बयान में कहा, "बीएसएफ और बीजीबी कर्मियों ने समय पर हस्तक्षेप किया और स्थिति पर तत्काल काबू पाया। दोनों पक्षों के किसानों को तितर-बितर कर दिया गया और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में वापस भेज दिया गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।" बीएसएफ ने इस तरह के विवादों से बचने पर जोर दिया और भारतीय किसानों को सलाह दी कि वे सीमा पर कृषि संबंधी किसी भी समस्या की सूचना सीधे बल के कर्मियों को दें। बयान में कहा गया, "हमने भारतीय किसानों से शांति बनाए रखने और सीमा विवादों में शामिल होने से बचने का अनुरोध किया है। किसी भी शिकायत के मामले में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।" सीमा पर बीजीबी ने भी स्थिति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। दोपहर बाद तक कुछ बांग्लादेशी नागरिक अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50-75 मीटर के दायरे में देखे गए, लेकिन खबरों के मुताबिक बीजीबी कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिससे स्थिति नहीं बिगड़ी। बयान के मुताबिक बीएसएफ और बीजीबी के इलाके में तैनात कमांडेंट भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के वास्ते समन्वय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।



## हल्दी आयोग यानी कृषि की ठोस नीति

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की है। गंगा रेड्डी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे हल्दी की उन्नतशील खेती में किसानों को जहाँ मदद मिलेगी, दूसरी तरफ वैश्विक बाजार पर भारत का सौ फीसदी कब्जा होगा क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादन और खपत करने वाला देश है। वैश्विक जरूरत की 70 फीसदी की आपूर्ति भारत करता है। हल्दी के निर्यात को पांच साल में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हल्दी हमारे संस्कृति और संस्कार में बसी है। हाथ पीले करने के लिए हल्दी आवश्यक है। हमारे यहाँ हल्दी को शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ कोई भी संस्कार बगैर हल्दी के संम्पन्न नहीं होता है। जीवन के आगमन और महाप्रयाण में भी हल्दी का अपना महत्व है। हल्दी आयुर्वेद की सबसे गुणकारी औषधि है यह एंटीबायोटिक भी है लेकिन अब भारतीय हल्दी किसानों के लिए एक अच्छी खबर आयी है। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों की 40 सालों से चली आ रही लबी मांग को मान लिया है। सरकार ने हल्दी आयोग (जन्तउमतपब ढवतक) का गठन करने की अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामबाद में होगा। देश के हल्दी किसान जहाँ संवृद्ध होंगे, वहीं हल्दी निर्यात में भारत का अपना दबदबा होगा। भारत में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। आयोग के गठन से जहाँ हल्दी की नई -नई प्रजातियों का विकास होगा। इसके अलावा हल्दी का कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक होगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी शोध के जरिए जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता से हल्दी की नई प्रजाति का विकास कर इसके उत्पादन को और व्यापक बनाया जा सकता है। इससे जहाँ हल्दी के किसानों की आय दोगुनी होगी, वहीं दुनिया के हल्दी बाजार पर भारत का एकाधिकार होगा। देश के तकरीबन 20 राज्यों में हल्दी की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। हल्दी निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी। सरकार को परम्परागत कृषि को संवृद्ध करने के साथ साथ औषधीय खेती और दूसरे कृषि उत्पाद पर भी इस तरह के आयोग का गठन करना चाहिए जिसका प्रभाव दुनिया के कृषि बाजार पर व्यापक होगा। देश का किसान जहाँ आर्थिक रूप से संवृद्ध होगा और दूसरी तरफ भारतीय कृषि उत्पादों का एकाधिकार बढ़ेगा। कृषि के वैश्विक बाजार पर पकड़ बनाने के लिए भारत के पास अपार संभावनाएँ हैं। अब सरकार किसानों के लिए कितना कुछ करती है, यह उस पर निर्भर है। भारत में गत वर्ष यानी 2023-2024 में 3.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हल्दी की खेती कर 10.74 लाख टन उत्पादन किया गया। हमारे यहाँ हल्दी की तीन प्रजातियों की खेती की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी और इस दौरान उत्पादन 11.61 लाख टन रहा था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है और यहां हल्दी की 30 किस्में उत्पादित दुनिया के हल्दी उत्पादन में भारत अग्रणी है। यह विश्व के कुल हल्दी उत्पादन का 60 से 70 फीसदी उत्पादन किया जाता है। साल 2022 और 2023 में 380 देशों को हल्दी और उससे जुड़े उत्पादों का निर्यात किया गया जिससे 207.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई। भारत के प्रमुख हल्दी आयातकों में अमेरिका, यूएई, मलेशिया और बांग्लादेश शामिल हैं। हल्दी आयोग का गठन निश्चित रूप से एक खुली पारदर्शी कृषि नीति है। हल्दी की खेती करने वालों के लिए एक सुखद परिणाम लेकर आएगी। सरकार को इस तरह की और खेती को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि नीति को और कारगर और प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। खेती में सरकार के पास असीमित शोध का क्षेत्र है। वैश्विक बाजार का अध्ययन कर देश को खेती के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करनी होगी। हमें किसानों के लिए ऐसा कृषि विकल्प खोजने की जरूरत है जिसमें लागत कम हो और किसानों को लाभकारी मूल्य मिले जिससे जहाँ किसान आर्थिक आमदनी में होंगे, वहीं नयी खेती की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। इसके अलावा भारत को मौसम, मृदा और जलवायु के हिसाब से कृषि क्षेत्र में विभाजित कर कृषि निर्धारण कारगर चाहिए।

## दिल्ली: राकांपा ने विधानसभा चुनाव के लिए 30 उम्मीदवार मैदान में उतारे

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा नजरअंदाज किये जाने से नाराज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 30 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की। राकांपा नेता इस बात से नाराज हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र के अपने प्रमुख सहयोगी दल को नजरअंदाज किया जबकि बिहार में जनता दल-यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को एक-एक सीट दे दी। अजित पवार नीत राकांपा ने जिन 30 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है उनमें से 13 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। राकांपा प्रवक्ता बुजमोहन श्रीवास्तव ने कहा, "हमारा मानना है कि ये 30 उम्मीदवार पार्टी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और दिल्ली में विकास और शहदारा सहित के लिए प्रतिबद्ध हैं।"राकांपा ने नई दिल्ली सीट से विश्वनाथ अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां से आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने इस सीट से लोकसभा के पूर्व सदस्य प्रवेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है जबकि कांग्रेस ने सदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। कालकाजी सीट पर राकांपा ने जमील को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और भाजपा उम्मीदवार रमेश बिड़ुड़ी के खिलाफ मैदान में उतारा है। राकांपा ने मटिया महल, मादीपुर, हरि नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, संगम विहार, तुगलकाबाद, बदरपुर, लक्ष्मी नगर और शहदारा सहित के लिए सीट पर भाजपा उम्मीदवार उतारे हैं। इससे पहले, राकांपा ने चुनाव में प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। दिल्ली की 70 संसदीय विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान पांच फरवरी को होगा और मतगणना आठ फरवरी को होगी।

## महाकुम्भ में सात करोड़ से अधिक रुद्राक्ष से निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए उमड़े भक्त

महाकुम्भ नगर, (भाषा) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ मेले के शिव नगरी में सात करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। महाकुम्भ के सेक्टर छह में निर्मित प्रत्येक ज्योतिर्लिंग 11 फुट ऊंचा, नौ फुट चौड़ा और सात फुट मोटा है, जिन्हें सात करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मणियों की माला पहनाई गई है। इन रुद्राक्ष को 10,000 गाँवों से पैदल घूम घूमकर भिक्षा में एकत्रित किया गया है। मौनी बाबा ने खुले आकाश में बने इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में "पीटीआई-भाषा" से जानकारी साझा करते हुए बताया, "आतंकवाद के नाश और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना से पूजा अनुष्ठान कर लौह से शिवलिंग को आकार दिया और उन पर रुद्राक्ष की मालाओं को लपेटा गया।" उन्होंने वर्णों पहले मन में रुद्राक्ष के ज्योतिर्लिंग की स्थापना का संकल्प लिया था। पिछले 37 वर्षों से मैं रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहा हूँ। यहां स्थापित ज्योतिर्लिंगों में एक मुखी से लेकर 26 मुखी तक के श्वेत रुद्राक्ष, काले रुद्राक्ष, लाल रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। " मौनी बाबा ने बताया कि यह रुद्राक्ष से बनी शिव नगरी पूरी दुनिया में अपनी तरह की अनूठी नगरी है, जहां छह शिवलिंग दक्षिणमुखी और छह शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पूरी दुनिया में महाकाल का अकेला शिवलिंग दक्षिण मुखी है। मौनी बाबा ने बताया कि रुद्राक्ष एक मूर्ति की तरह होता है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और बिना प्राण प्रतिष्ठा के रुद्राक्ष पहना नहीं जा सकता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही रुद्राक्ष मनोकामनाओं की पूर्ति करता है।

## अब ईपीएफओ के सदस्य खुद ही कर सकेंगे निजी जानकारियों में संशोधन

नयी दिल्ली, (भाषा) सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के 7.6 करोड़ से अधिक सदस्य अब नियोक्ता द्वारा किसी सत्यापन या ईपीएफओ की मंजूरी के बगैर भी नाम और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियों में ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। यह सुविधा शनिवार से शुरू हो गई। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ई-केवाईसी ईपीएफ खाते (आधार से जुड़े) वाले सदस्य, नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के साथ सीधे अपने ईपीएफ हस्तांतरण दावे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को ईपीएफओ की इन दोनों नई सेवाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ सदस्यों द्वारा दर्ज लगभग 27 प्रतिशत शिकायतें सदस्य प्रोफाइल / केवाईसी मुद्दों से संबंधित हैं और इस सुविधा के शुरू होने के बाद इन शिकायतों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरणों में संशोधन के अनुरोधों का लाभ भारी कार्यबल वाले बड़े नियोक्ताओं को भी होगा। श्रम मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ ने ईपीएफओ पोर्टल पर संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इससे कर्मचारियों को नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/ पत्नी का नाम, कामकाजी संगठन से जुड़ने और छोड़ने की तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियों में होने वाली आम त्रुटियों को खुद ही सुधारने की सुविधा मिल गई है। इसके लिए नियोक्ता द्वारा किसी सत्यापन या ईपीएफओ द्वारा अनुमोदन की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे मामलों में किसी सहयोगी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका यूपएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) एक अक्टूबर, 2017 (जब आधार से निलान अनिवार्य हो गया था) के बाद जारी किया गया था। यूपएन एक अक्टूबर, 2017 से पहले जारी होने की स्थिति में नियोक्ता ईपीएफओ की मंजूरी के बिना भी विवरण को सही कर सकता है। ऐसे मामलों के लिए सहयोगी दस्तावेज की जरूरत को भी सरल बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि केवल उन मामलों में जहां यूपएन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, वहां किसी भी सुधार को नियोक्ता के समक्ष भौतिक रूप से प्रस्तुत करना होगा तथा सत्यापन के बाद अनुमोदन के लिए ईपीएफओ को भेजना होगा। यूपएन पंजीकरण नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए शुरुआत में किया जाता है। कई कर्मचारियों के लिए, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान या बाद में पिता/पति या पत्नी का नाम, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता और सेवा विवरण दर्ज करने में नियोक्ताओं द्वारा गलतियों की गईं। इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए कर्मचारी को सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अनुरोध करना पड़ता था। इस अनुरोध को नियोक्ता द्वारा सत्यापित करना होता था और उसे अनुमोदन के लिए ईपीएफओ को भी भेजा जाता था।

## हल्दी आयोग यानी कृषि की ठोस नीति



केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की है। गंगा रेड्डी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे हल्दी की उन्नतशील खेती में किसानों को जहाँ मदद मिलेगी, दूसरी तरफ वैश्विक बाजार पर भारत का सौ फीसदी कब्जा होगा क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादन और खपत करने वाला देश है। वैश्विक जरूरत की 70 फीसदी की आपूर्ति भारत करता है। हल्दी के निर्यात को पांच साल में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हल्दी हमारे संस्कृति और संस्कार में बसी है। हाथ पीले करने के लिए हल्दी आवश्यक है। हमारे यहाँ हल्दी को शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ कोई भी संस्कार बगैर हल्दी के संम्पन्न नहीं होता है। जीवन के आगमन और महाप्रयाण में भी हल्दी का अपना महत्व है। हल्दी आयुर्वेद की सबसे गुणकारी औषधि है यह एंटीबायोटिक भी है लेकिन अब भारतीय हल्दी किसानों के लिए एक अच्छी खबर आयी है। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों की 40 सालों से चली आ रही लबी मांग को मान लिया है। सरकार ने हल्दी आयोग (जन्तउमतपब ढवतक) का गठन करने की अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामबाद में होगा। देश के हल्दी किसान जहाँ संवृद्ध होंगे, वहीं हल्दी निर्यात में भारत का अपना दबदबा होगा। भारत में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। आयोग के गठन से जहाँ हल्दी की नई -नई प्रजातियों का विकास होगा। इसके अलावा हल्दी का कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक होगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी शोध के जरिए जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता से हल्दी की नई प्रजाति का विकास कर इसके उत्पादन को और व्यापक बनाया जा सकता है। इससे जहाँ हल्दी के किसानों की आय दोगुनी होगी, वहीं दुनिया के हल्दी बाजार पर भारत का एकाधिकार होगा। देश के तकरीबन 20 राज्यों में हल्दी की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। हल्दी निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी। सरकार को परम्परागत कृषि को संवृद्ध करने के साथ साथ औषधीय खेती और दूसरे कृषि उत्पाद पर भी इस तरह के आयोग का गठन करना चाहिए जिसका प्रभाव दुनिया के कृषि बाजार पर व्यापक होगा। देश का किसान जहाँ आर्थिक रूप से संवृद्ध होगा और दूसरी तरफ भारतीय कृषि उत्पादों का एकाधिकार बढ़ेगा। कृषि के वैश्विक बाजार पर पकड़ बनाने के लिए भारत के पास अपार संभावनाएँ हैं। अब सरकार किसानों के लिए कितना कुछ करती है, यह उस पर निर्भर है। भारत में गत वर्ष यानी 2023-2024 में 3.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हल्दी की खेती कर 10.74 लाख टन उत्पादन किया गया। हमारे यहाँ हल्दी की तीन प्रजातियों की खेती की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी और इस दौरान उत्पादन 11.61 लाख टन रहा था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है और यहां हल्दी की 30 किस्में उत्पादित दुनिया के हल्दी उत्पादन में भारत अग्रणी है। यह विश्व के कुल हल्दी उत्पादन का 60 से 70 फीसदी उत्पादन किया जाता है। साल 2022 और 2023 में 380 देशों को हल्दी और उससे जुड़े उत्पादों का निर्यात किया गया जिससे 207.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई। भारत के प्रमुख हल्दी आयातकों में अमेरिका, यूएई, मलेशिया और बांग्लादेश शामिल हैं। हल्दी आयोग का गठन निश्चित रूप से एक खुली पारदर्शी कृषि नीति है। हल्दी की खेती करने वालों के लिए एक सुखद परिणाम लेकर आएगी। सरकार को इस तरह की और खेती को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि नीति को और कारगर और प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। खेती में सरकार के पास असीमित शोध का क्षेत्र है। वैश्विक बाजार का अध्ययन कर देश को खेती के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करनी होगी। हमें किसानों के लिए ऐसा कृषि विकल्प खोजने की जरूरत है जिसमें लागत कम हो और किसानों को लाभकारी मूल्य मिले जिससे जहाँ किसान आर्थिक आमदनी में होंगे, वहीं नयी खेती की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। इसके अलावा भारत को मौसम, मृदा और जलवायु के हिसाब से कृषि क्षेत्र में विभाजित कर कृषि निर्धारण कारगर चाहिए।



# पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही है निक्की तंबोली



फिल्म 'कंचना 3' में दिव्या के रूप में उन्होंने तमिल में डेब्यू किया। उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म तेलुगु में बनी थिप्पारा मीसम थी। वह अब तक तमिल और तेलुगु की आधा दर्जन से अधिक फिल्मों कर चुकी हैं। 2020 में निक्की ने सलमान खान के हिंदी रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में भाग लेते हुए टेलीविजन डेब्यू किया। इस रियलिटी शो में वह तीसरे स्थान पर रहीं। निक्की को इस रियलिटी शो से अत्यधिक फेम मिला। इस शो के जरिए वह देश भर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं। 'बिग बॉस 14' में हिस्सा लेने के बाद से ही निक्की लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं। यह शो उनके लिए एक 'टर्निंग प्वाइंट' जैसा था क्योंकि इससे पहले उन्हें साउथ की एक्ट्रेस के तौर पर लोग ज्यादा नहीं जानते थे। 2021 में निक्की ने स्टंट-आधारित रियलिटी शो फियर फ़ैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 11 में ने भाग लेकर 10 वां स्थान हासिल किया। 2022 में वह भारतीय सिंह और हर्ष लिंबाचिया द्वारा होस्ट किए गए गेम शो 'द खतरा खतरा' में नजर आईं। इस शो में काम करते हुए उनका नाम प्रतीक सहजपाल के साथ जुड़ा। पिछले साल निक्की तंबोली अपने अफेयर की खबरों को लेकर काफी अधिक सुर्खियों में रहीं। 2024 की शुरुआत में जहां उनका नाम बिजनेस मैन मनन शाह के साथ अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहा। वहीं साल खत्म होते होते अरबाज पटेल के साथ उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि आज दोनों के बीच काफी करीबी रिश्ता बन चुका है। दोनों की मुलाकात रियलिटी शो 'बिग बॉस मराठी सीजन 5' के दौरान हुई थी। निक्की ने वेब सीरीज 'पपी लव' के साथ ओटीटी पर डेब्यू किया। इसमें निक्की ने तनुज विरवानी के अपोजिट एक पंजाबी एनआरआई के शानदार किरदार में नजर आई थीं। फिलहाल निक्की के पास कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है लेकिन लोगों का मानना है कि जिस तरह से वह सोशल मीडिया पर खुद को प्रस्तुत कर रही हैं, उसके पीछे उनकी मुख्य स्ट्रेटजी यही है कि वह किसी भी तरह बॉलीवुड की फिल्मों में व्यस्त हो जाए। उनका लैमरस अवतार कर किसी की धड़कन को बढ़ाता रहता है। अपनी बोलनेस की वजह से सोशल मीडिया पर वह अक्सर सनसनी मचाती रहती हैं। अपने परफेक्ट फिगर के लिए वह बेहद मशहूर हैं। खासकर उनकी बेहद पतली कमर को देखकर हर किसी को अचरज होता है कि आखिर उनका फिगर इतना परफेक्ट कैसे है ?

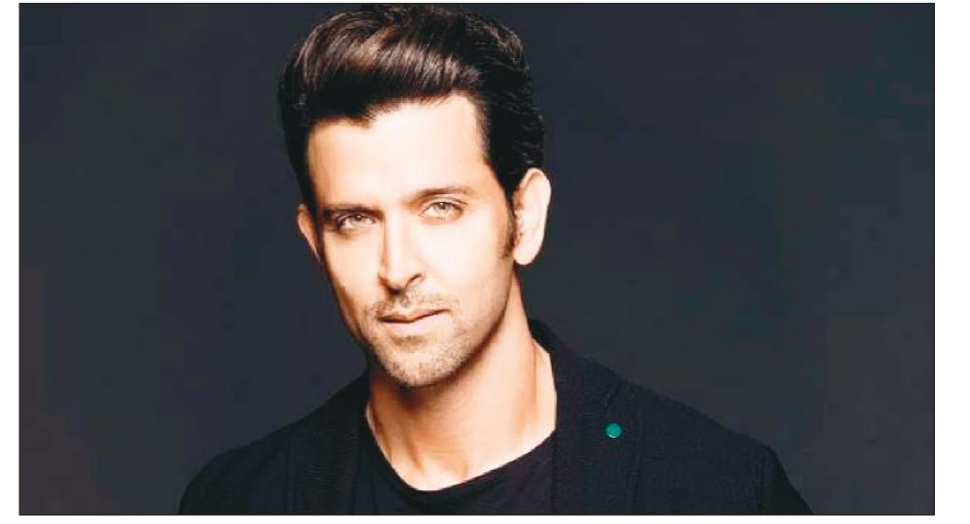
'बिग बॉस 14' की प्रतियोगी रह चुकी ग्लैमर वर्ल्ड की खूबसूरत एक्ट्रेस निक्की तंबोली, जय रंधावा, जैस्मीन भसीन और मुकेश ऋषि लीड रोल वाली पंजाबी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'बदनाम' के जरिए पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में निक्की का एक बेहद जोरदार आइटम सॉन्ग होगा। निक्की तंबोली इसके पहले भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हिंदी फिल्म 'जोगीरा सारा रा रा' के आइटम सांग 'कॉकटेल....' में नजर आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर निक्की के फैंस की तादाद लाखों में है। शायद इसी को देखते हुए फिल्म 'बदनाम' की शूटिंग खत्म होने

के बाद फिल्म में निक्की के आइटम सांग की प्लानिंग की गई। इस गाने को सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज दी है। यह फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है। निक्की फिल्म 'बदनाम' का हिस्सा बनकर बेहद रोमांचित हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया आकाउंट पर दावा किया है कि उन पर फिल्माया गया यह एक ऐसा डांस नंबर होगा, जो सिनेमा हॉल में हर किसी को उठकर नाचने पर मजबूर कर देगा। एक मॉडल के तौर पर अपना करियर शुरू करने के बाद निक्की ने तेलुगू हॉरर कॉमेडी फिल्म 'चिकाती गडिलो चिथाकोटुडु' (2019) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। एक्शन हॉरर

**सैफ ने हाल में 'ज्वेल थीफ' की शूटिंग पूरी की, 'कर्तव्य' और 'रेस4' में भी नजर आएंगे**

**मुंबई, (भाषा)** चाकू हमले में घायल होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में चोटों से उबर रहे बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने हाल में अपनी अगली फिल्म 'ज्वेल थीफ— द रेड सन चैप्टर' की शूटिंग पूरी की और उनके पास कुछ अन्य परियोजनाएं भी हैं। अभिनेता पर बुधवार देर रात बांद्रा स्थित उनके घर में घुसे एक हमलावर ने चाकू से कई वार किये थे, जिसमें उनकी गर्दन पर और शीर्ष की हड्डी के नजदीक चोटें आईं। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी अपातकालीन सर्जरी की गई। सैफ हाल में जूनियर एनटीआर की 'देवरा : पार्ट 1' में नजर आये थे, जो सितंबर 2024 में देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सैफ के इस फिल्म के अगले भाग में भी नजर आने की उम्मीद है। हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक दूसरे भाग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अभिनेता की आगामी फिल्म 'ज्वेल थीफ— द रेड सन चैप्टर' एक डकैती पर आधारित है। रॉबी ग्रेवाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जयदीप अहलावत भी हैं। एक सूत्र के अनुसार, अभिनेता ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, जो मार्च 2025 में रिलीज होने वाली है। 'ज्वेल थीफ' के अलावा, खान 'कर्तव्य' में भी नजर आएंगे, जो 'भक्षक' के निर्देशक पुलकित की आगामी फिल्म है। निर्देशक ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'सैफ अभिनीत फिल्म तैयार है, हम रिलीज पर काम कर रहे हैं। रिलीज की तारीख निर्माता ही बताएंगे।'

**ऋतिक रोशन ने अपनी वाणिज्यिक संपत्ति को 5.62 लाख रुपये के किराये पर दिया**



**नयी दिल्ली,** बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने मुंबई स्थित अपनी प्रीमियम कर्माशियल प्रॉपर्टी को 5.62 लाख रुपये प्रति महीने के किराये पर दिया है। रियल एस्टेट परामर्शदाता स्ववायर यादर्स ने शनिवार को बताया कि उसने इस संपत्ति पंजीकरण के दस्तावेजों की समीक्षा की है। उसने कहा, 'ऋतिक रोशन ने अपनी प्रीमियम वाणिज्यिक संपत्ति को किराये पर दिया है, जिससे उन्हें 5.62,000 रुपये की मासिक आय हो रही है।' यह वाणिज्यिक संपत्ति मुंबई के गोरेगांव में विकसित लोटस कॉरपोरेट पार्क परियोजना में स्थित है। लगभग 27.55 एकड़ में फैली यह परियोजना आधुनिक कार्यालय स्थान प्रदान करती है।

**मुंबई में कोल्डप्ले की प्रस्तुति से पहले क्रिस मार्टिन, डकोटा जॉनसन बाबुलनाथ मंदिर पहुंचे**



**मुंबई, (भाषा)** ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले के नवी मुंबई में पहले संगीत कार्यक्रम से पहले इसके प्रमुख गायक क्रिस मार्टिन और उनकी दोस्त हॉलीवुड स्टार डकोटा जॉनसन ने प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें मार्टिन और जॉनसन शुकवार को भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में जॉनसन (35) मंदिर में नंदी की मूर्ति के कान में फुसफुसाते हुए दिखाई दे रही हैं। मार्टिन (47) ने नीला कुर्ता पहना हुआ था, जबकि जॉनसन ने प्रिंटेड सूट पहना हुआ था और अपने सिर को दुपट्टे से ढका हुआ था। दोनों को ऐसे वक्त साथ देखा गया है जब कुछ समय पहले जोड़े के रिश्ते टूटने की अफवाह फैली थी। मार्टिन और जॉनसन 2017 से प्रेम संबंध में हैं। 'द सोशल नेटवर्क', 'सस्पिरिया' और 'द लॉस्ट डॉक्टर' जैसी फिल्मों की अभिनेत्री जॉनसन भारत में कोल्डप्ले के 'म्यूजिक ऑफ द स्कीयर्स वर्ल्ड टूर' के लिए मार्टिन के साथ हैं। शनिवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में बैंड की पहली प्रस्तुति होगी। कोल्डप्ले 19 और 21 जनवरी को मुंबई में दो और कार्यक्रम करेगा। चौथा कार्यक्रम 25 जनवरी को अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में होगा। ब्रिटिश बैंड ने इससे पहले 2016 में मुंबई में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में भारत में प्रस्तुति दी थी।

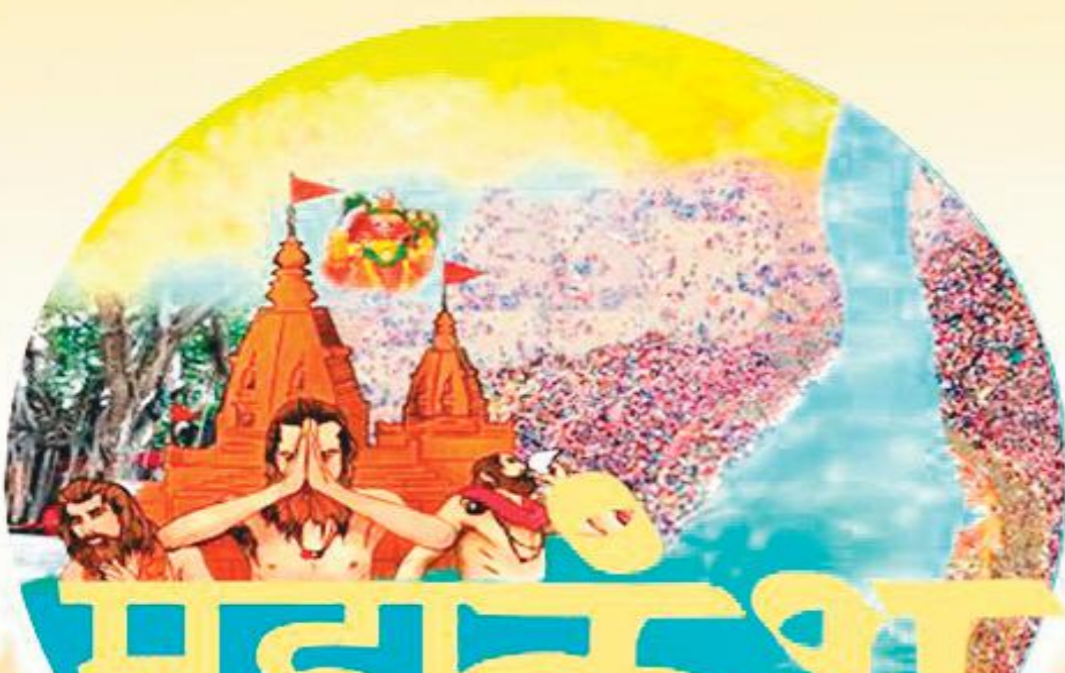


**Here's your chance to celebrate Mahakumbh 2025 your way!**



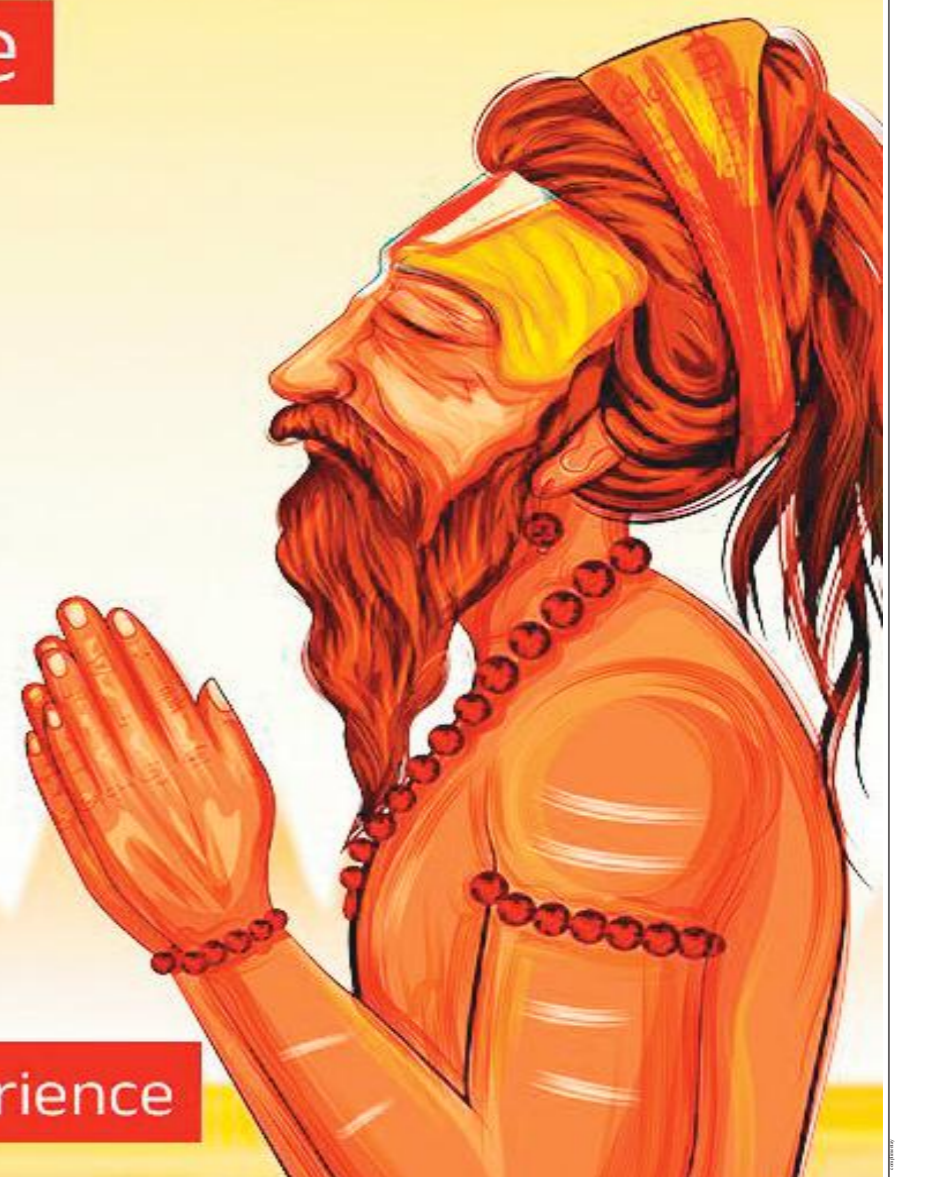
**Participate in**

**Various Activities & make**



**महाकुम्भ 2025**

**an unforgettable experience**



**नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं: सीडीएससीओ नयी दिल्ली, (भाषा)** पहले इस्तेमाल किए जा चुके चिकित्सा उपकरणों के देश में अनियमित प्रवाह को रोकने के लिए शीर्ष औषधि नियामक सीडीएससीओ ने सीमा शुल्क विभाग को सूचित किया है कि नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं है। सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त को लिखे पत्र में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने कहा है कि सभी चिकित्सा उपकरणों को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत विनियमित किया जाता है। सीडीएससीओ ने कहा, “हालांकि, उक्त नियमों के तहत नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के विनियमन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए, ऐसे उपकरणों के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है और इन्हें बिक्री तथा वितरण के लिए चिकित्सा उपकरण नियमों के तहत आयात नहीं किया जा सकता है।” चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णायक स्पष्टीकरण रोगी सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए डिजायन किए गए नियामकीय ढांचे को मजबूत करता है। पीएचडीसीसीआई में चिकित्सा उपकरण समिति के पूर्व चेयरपर्सन डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि सीडीएससीओ का यह निर्णय चिकित्सा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रीवास्तव ने कहा, “देश में नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों को अनुमति देने से स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता खतरे में पड़ जाती, स्थानीय नवाचार हतोत्साहित होता और ‘मेक इन इंडिया’ पहल की भावना कमजोर होती।” इनवॉल्यूशन हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक गौरव अग्रवाल ने कहा कि सीडीएससीओ का निर्णायक स्पष्टीकरण नियामक ढांचे को मजबूत करता है, जो रोगी सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए डिजायन किया गया है। इसके साथ ही स्वदेशी विनिर्माण की वृद्धि के लिए एक मजबूत माहौल भी तैयार करता है।

**झारखंड का ऋण–जमा अनुपात 50 प्रतिशत के पार, मार्च तक 55 प्रतिशत करने की योजना: एसएलबीसी रांची, (भाषा)** झारखंड की राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) ने शनिवार को निर्णय लिया कि मार्च के अंत तक ऋण–जमा अनुपात को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया जाएगा। एसएलबीसी की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक एम कार्तिकेयन ने की। बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और वित्त सचिव प्रशांक कुमार भी उपस्थित थे। किशोर ने कहा, “राज्य में ऋण–जमा अनुपात में वृद्धि हुई है, लेकिन यह राष्ट्रीय औसत 87 प्रतिशत की तुलना में अभी भी कम है।” बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय को झारखंड से बिहार के पटना में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई। मंत्री ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “झारखंड में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 120 शाखाएं हैं, जिनमें कुल जमा राशि 13,555 करोड़ रुपये है। बिहार में इसकी 236 शाखाएं हैं, जिनमें जमा राशि 15,743 करोड़ रुपये है। मैंने बैंक अधिकारियों से पूछा है कि झारखंड में जमा राशि अधिक होने पर भी बैंक को स्थानांतरित करने का क्या कारण है। यह झारखंड के हितों के खिलाफ है और स्वीकार्य नहीं है।” स्वागत भाषण में एसएलबीसी के महाप्रबंधक एवं बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय महाप्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि झारखंड का ऋण–जमा अनुपात पहली बार 50 प्रतिशत को पार कर 30 सितंबर, 2024 तक 50.22 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह दर्शाता है कि राज्य में बैंक ऋण प्रवाह में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। राज्य में ऋण–जमा अनुपात 30 सितंबर, 2024 को 50.22 प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि 30 सितंबर, 2023 को यह 45.04 प्रतिशत था।

## बिहार : वक्फ संशोधन विधेयक—2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई

**पटना, (भाषा)** वक्फ संशोधन विधेयक— 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक शनिवार को पटना में हुई, जिसकी अध्यक्षता जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने की। बैठक की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल ने की और इसमें सदस्यों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। जेपीसी समिति द्वारा विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार और यह सुनिश्चित करने के लिए उस राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित के लिए किया जाए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बिहार इकाई के मीडिया समन्वयक दानिश इकबाल ने भी बैठक में भाग लिया। इकबाल ने एक बयान में विधेयक को वंचित और पिछड़े मुसलमानों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और इस बात पर जोर दिया कि इसके कार्यान्वयन से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगेगा। बैठक के दौरान इकबाल ने वक्फ बोर्ड में गैर–मुस्लिमों को शामिल करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और इसे एक प्रगतिशील और संतुलित कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर–मुस्लिमों में केवल हिंदू ही नहीं इस्लाम, सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हैं।

### मद्र राज्य सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित, शीर्ष 10 में छह महिलाएं शामिल

**इंदौर, (भाषा)** मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम शनिवार शाम घोषित किया और शीर्ष 10 सफल उम्मीदवारों में छह महिलाओं ने जगह बनाई है। एमपीपीएससी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घोषित परिणाम के मुताबिक दीपिका पाटीदार राज्य सेवा परीक्षा 2022 में शीर्ष स्थान पर रहीं और उप जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) पद पर चयनित हुईं। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी पद पर चयनित शीर्ष 10 उम्मीदवारों में क्रमशः आदित्य नारायण तिवारी, सुरभि जैन, महिमा चौधरी, धर्मप्रकाश मिश्रा, शानू चौधरी, स्वाति सिंह, उमेश अवस्थी, कविता देवी यादव और प्रत्युष श्रीवास्तव शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए मूल्यांकित: 456 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था लेकिन सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मुकदमा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण फिलहाल इनमें से 87 प्रतिशत पदों का चयन परिणाम घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष 13 प्रतिशत पदों की चयन सूची इस मुकदमे में अदालत के अंतिम फैसले के बाद घोषित की जाएगी।

**पोषण संबंधी सहायता से भारत में 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों और मामलों को रोका जा सकता है :अध्ययन नयी दिल्ली, (भाषा)** भारत में क्षय रोग (टीबी) का उपचार करा रहे रोगियों वाले आधे परिवारों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने से 2035 तक टीबी से संबंधित 4.5 प्रतिशत मौतों और 2.2 प्रतिशत ऐसे मामलों को कम किया जा सकता है। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। “ द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल ” में प्रकाशित अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि इस तरह के प्रयास से 3.6 लाख से अधिक मौतों और 8.8 लाख से अधिक टीबी के मामलों को रोका जा सकता है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि आमतौर पर मौत के एक मामले को रोकने के लिए लगभग 24 परिवारों को तपेदिक का उपचार कराने की आवश्यकता होगी जबकि एक मामले को रोकने के लिए 10 परिवारों को उपचार कराने की जरूरत होगी।

# बाल कथा— बर्गर

छुट्टी वाले दिन अलमर् का शोर कितना सुहाना लगता है। यह कोई दस साल के हर्ष से पूछे। काश ऐसा बाल दिवस रोज आये, स्कूल की छुट्टी हो और मम्मी पापा ने बाजार घूमाने का वादा किया हो। वाह हुई न मजेदार बात। इतेफाक से आज आनंद की भी दफ्तर से छुट्टी थी। शायद पिछले संडे आफिस में बैठकर काम करने का इनाम। तो आदतन सुबह सात बजे उनकी भी नींद खुल तो गयी मगर छुट्टी का ख्याल आते ही अंतर्मन तक शांति और सुख का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे जन्त क पहलव हो गयी हो और हो भी क्यों न आखिर मिड वीक आफ यानी मध्य सप्ताह छुट्टी की बात ही अलग होती है। सो बस आँखें मीचे बिस्तर में ऊँघते रहे। उधर रश्मि का भी मन अति आनंदित था – न बेटे का स्कूल न पति का आफिस। उसपर घूमने जाने की खुशी अलग। दिल्ली का वर्मा परिवार आज असल मायनों में सुख सागर में गोते लगा रहा था। पापा हम हमेशा आपकी वजह से लेट होते हैं। अभी तक आप नहाये भी नहीं। अभी नहाने ही जा रहा हूँ। तो जाइये न।

उफ ये लड़का! आज जरा तसल्ली से अखबार तो पढ़ने दे बेटा। देखा! अब अखबार पढ़ने लगे। पापा ऐसे तो हम शाम तक भी नहीं जा पायेंगे, आप जानते हैं मुझे नई बैट्री वाली गाडी खरीदनी है, जैसी गगन के पास है, और सबसे जरूरी दू बर्गर! अच्छा बाबा जा रहा हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।

हर्ष – मम्मी आप भी अपना फोन रख के मुझे जल्दी से तैयार कर दीजिये।
मम्मी – जरा एक मिनट बेटे, ये नया व्हाट्सएप आया है बाल दिवस पर। जरा

# किसानों को धान का बोनस देने से पहले ड्रोन से सर्वेक्षण कराएंगे: मप्र मुख्यमंत्री



का ड्रोन सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है।” धान बोनस का मतलब आमतौर पर फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि से है। उन्होंने कहा, “हम बोनस की राशि सभी किसानों के बैंक खाते में डालेंगे। कोई भी वंचित नहीं रहेगा।” यादव ने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प ‘हर खेत को पानी और हर हाथ को काम’ उपलब्ध कराना है। राज्य की पिछली कांग्रेस सरकारों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 1956 से 2003 के बीच विपक्ष दल के कार्यकाल में राज्य की सिंचाई क्षमता सिर्फ सात लाख हेक्टेयर थी। मुख्यमंत्री ने कहा, “लेकिन 2003 से 2023 तक भाजपा के सत्ता में रहने के बाद सिंचाई क्षमता 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। अब हमारी सरकार ने अगले पांच वर्षों में सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर एक करोड़ हेक्टेयर करने का संकल्प लिया है।” उन्होंने कहा, “हमने 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। इस साल एक लाख पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।”

## मप्र में सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कर्मों की पांच करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा

**उज्जैन, (भाषा)** मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शनिवार को उज्जैन में जिलों सहकारी बैंक के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के घर की तलाशी के दौरान पांच करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का पता लगाने का दावा किया। ईओडब्ल्यू अधिकारियों को जिला सहकारी बैंक के पूर्व सहायक प्रबंधक अनिल सुहाने के अवासे से पांच लाख रुपये नकद मिले। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले महीने की शुरुआत में सेवानिवृत्त हुए सुहाने को उसकी सेवा के दौरान लगभग 70 लाख रुपये वेतन मिला था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को तलाशी और बैंक लॉकरों के बारे में जानकारी से पांच करोड़ रुपये की कथित आय से अधिक संपत्ति का पता चला। उन्होंने बताया कि उज्जैन शहर में सुहाने से जुड़े अन्य स्थानों पर भी तलाशी ली जा रही है। अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने एक व्यावसायिक भूखंड और पांच लाख रुपये नकद सहित अन्य संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि संपत्तियों के मूल्य का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए बैंक लॉकर खोले जाएंगे।

## एएआई ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण: खजुराहो मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, देशभर में आठवां स्थान



कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे निरंतर सुधारों को दर्शाती है। हम सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और खजुराहो हवाई अड्डे को यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाने का प्रयास जारी रखेंगे।” छतरपुर में स्थित खजुराहो देश के शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है।

### एएआई ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण: खजुराहो मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, देशभर में आठवां स्थान

**भोपाल, (भाषा)** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा किए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के अनुसार खजुराहो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बनकर उभरा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देशभर के 62 हवाई अड्डों की सूची में इसे आठवां स्थान मिला है जबकि ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर हवाई अड्डों को क्रमशः दसवां, 15वां और 22वां स्थान मिला है। खजुराहो हवाई अड्डे के निदेशक संतोष सिंह ने कहा, “यह उपलब्धि हमारे कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे निरंतर सुधारों को दर्शाती है। हम सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और खजुराहो हवाई अड्डे को यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाने का प्रयास जारी रखेंगे।” छतरपुर में स्थित खजुराहो देश के शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है।

### मप्र : संविधान–आंबेडकर रैलियों के जरिये भाजपा और कांग्रेस का होगा आमना–सामना



**भोपाल, (भाषा)** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस की संविधान और इसके निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर राजनीतिक लड़ाई जारी है और इसी कड़ी में अगले कुछ दिन में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम हैं। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित अन्य नेता पार्टी द्वारा शुरू ‘संविधान गौरव अभियान’ के तहत 20–21 जनवरी को जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक नेता ने शनिवार को ‘पीटीआई–भाषा’ को बताया कि इन नेताओं के कार्यक्रमों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। भाजपा ने 11 जनवरी को मध्य प्रदेश में ‘संविधान गौरव अभियान’ की शुरुआत की थी। कांग्रेस 27 जनवरी को इंदौर के पास बाबा साहब आंबेडकर की जन्मस्थली मूहू में एक जनसभा आयोजित करेगी जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में मध्य प्रदेश और अमित शाह के राजनीतिक मामलों के प्रभारी महासचिव जितेन्द्र सिंह ने पिछले सप्ताह कहा था कि मूहू में कांग्रेस संविधान और लोगों के अधिकारों को बचाने के उद्देश्य से ‘जय बापू–जय भीम–जय संविधान’ अभियान की शुरुआत करेगी।

आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मूहू की सैन्य छावनी में हुआ था, जिसे अब आधिकारिक तौर पर डॉ. आंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने ‘पीटीआई–भाषा’ को बताया, “संविधान गौरव अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं और वरिष्ठ नेता इसमें हिस्सा लेंगे। अभियान 25 जनवरी को समाप्त होगा।” इस बीच, कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव ने कहा कि पार्टी की 27 जनवरी की विशाल ‘रैली’ में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी)के सदस्य भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रैली में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी के नेतृत्व में तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ पार्टी 400 से अधिक सीट चाहती है ताकि संविधान में बदलाव कर आरक्षण को समाप्त किया जा सके। हाल में विपक्ष ने अमित शाह पर संसद में भाषण के दौरान आंबेडकर का ‘अपमान’ करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया था।

### केंद्र ने राज्यों, एथनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई चावल की कीमत 550 रुपये प्रति क्विंटल घटाई

**नयी दिल्ली, (भाषा)** केंद्र ने एफसीआई चावल का आरक्षित मूल्य शुक्रवार को राज्यों और एथनॉल उत्पादकों के लिए खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत 550 रुपये प्रति क्विंटल घटाकर 2,250 रुपये कर दिया। यह कदम इसकी बिक्री को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा उपायों का समर्थन करने के लिए उठाया गया है। खाद्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार, राज्य सरकारें और सरकारी निगम 12 लाख टन तक खरीद सकते हैं, जबकि एथनॉल डिस्टिलरी को कम दर पर 24 लाख टन तक खरीदने की अनुमति है। दोनों श्रेणियों के लिए पिछला आरक्षित मूल्य 2,800 रुपये प्रति क्विंटल था। साप्ताहिक ई–नीलामी के माध्यम से चावल के भंडारण का प्रबंधन करने वाला भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) 30 जून, 2025 तक संशोधित नीति को लागू करेगा। निजी व्यापारी और सहकारी समितियां 2,800 रुपये प्रति क्विंटल का मुामान कराने जारी रखेंगी, जबकि ‘भारत’ ब्रांड के तहत बिक्री करने वाली नैफेड, एनसीसीएफ और केन्द्रीय भंडार जैसी केन्द्रीय सहकारी समितियां 2,400 रुपये प्रति क्विंटल का मुामान करेगी। मंत्रालय ने आदेश दिया है कि 2024–25 के दौरान लगभग 110 करोड़ लीटर एथनॉल के लिए तीसरे चक्र की निविदा में एफसीआई चावल का उपयोग किया जाना चाहिए, जहां तक संभव हो, पुराने चावल के भंडारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ओएमएसएस के तहत राज्यों को चावल की बिक्री गैर–अधिेश क्षेत्रों तक सीमित है, जिन्हें अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता है। निजी मिल मालिकों को ‘भारत’ ब्रांड चावल की बिक्री की अनुमति नहीं है, लेकिन छात्रावासों, धार्मिक संस्थानों, अस्पतालों और धर्मार्थ संगठनों के लिए इसकी अनुमति है। यह संशोधन इसी योजना के तहत गेहूं की तुलना में चावल की अपेक्षाकृत कम बिक्री के बीच किया गया है, जिसका उद्देश्य खुले बाजार में उपलब्धता को बढ़ाना और कीमतों को स्थिर करना है।

## एनीमिया के ज्यादातर मामले आयरन की कमी के अलावा अन्य कारणों से : अध्ययन

**नयी दिल्ली, (भाषा)** देश के आठ राज्यों में सामुदायिक स्तर पर किये गए रक्त सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले एक अध्ययन के अनुसार, ‘एनीमिया’ के मामलों का एक बड़ा हिस्सा विटामिन बी12 की कमी और वायु प्रदूषण जैसे कारणों से जुड़ा पाया गया। हालांकि, एनीमिया आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। ‘यूरोपियन जर्नल ऑफ विलिनिकल न्यूट्रीशन’ में प्रकाशित अध्ययन से यह भी पता चला कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया कुल मामलों के एक तिहाई से भी कम हैं। ‘विटामिन बी12 इंडिया स्टडी’ और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय पोषण परिषद (आईसीएमआर–एनआईएन), हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कहा कि उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि एनीमिया के कारण के रूप में आयरन की कमी मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं लगती। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार, इस्तरह “इन परिणामों का एनीमिया की रोकथाम और सुधार के लिए नीतिगत निहितार्थ हैं।” अध्ययन के लेखकों के अनुसार, एनीमिया, एक रक्त विकार है जिसमें स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं अपर्याप्त होती हैं या खराब हो रही होती हैं। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है और माना जाता है कि यह और भी बढ़तर होती जा रही है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के रूझानों से पता चला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण एनीमिया के कारण की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि वे केवल उंचाली से लिये गए रक्त के नमूने के आधार पर केशिका रक्त हीमोग्लोबिन को मापते हैं। अध्ययन दल ने 2019 के व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण का हवाला दिया, जिसमें नर्सों से लिए गए भारतीय बच्चों के रक्त के नमूनों में हीमोग्लोबिन के स्तर का विश्लेषण किया गया था, और एनीमिया की कम व्यापकता पाई गई थी। हालांकि, अध्ययन के लेखकों ने कहा कि आयरन की कमी को एनीमिया का प्रमुख कारण माना जाता है। इस अध्ययन के लिए, पूर्वांतर, मध्य, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों से किशोरों, वयस्कों और बुजुर्गों सहित कुल 4,613 लोगों को शामिल किया गया था। अध्ययन के लेखकों के अनुसार, “नर्सों से लिए गये रक्त के नमूने पर आधारित सर्वेक्षण में, पुरुषों और महिलाओं में एनीमिया की मौजूदगी, उन्हीं राज्यों में केशिका रक्त–आधापरित एनएफएचएस–5 सर्वेक्षण के परिणामों से स्पष्ट रूप से कम पाया गया।” उन्होंने लिखा, “महिलाओं में, आठ राज्यों में एनीमिया का प्रसार 41.1 प्रतिशत था, जबकि एनएफएचएस–5 में 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए यह 60.8 प्रतिशत था।”

### मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इंदौर जिला न्यायालय में डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया

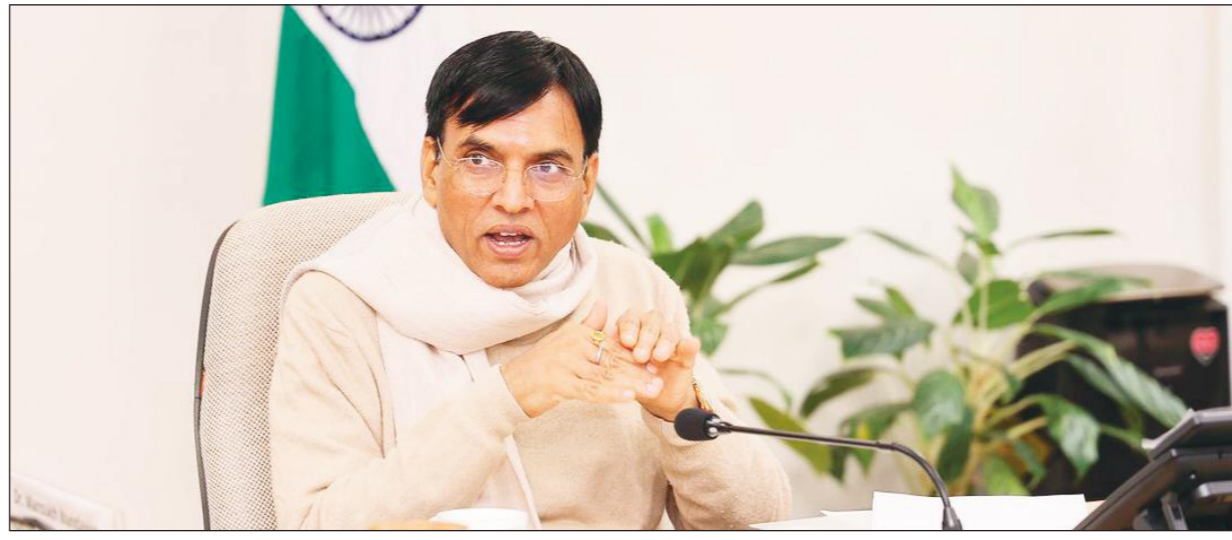
**इंदौर, (भाषा)** मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैंत ने इंदौर के जिला न्यायालय परिसर में बुधवार को डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया और कहा कि वकीलों के हित में हरसंभव कदम उठाया जाएगा। कैंत ने जिला न्यायालय परिसर में फीता काटकर डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक रूसिया भी मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैंत ने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा, “मेरे अनुरोध पर स्वास्थ्य विभाग ने जिला न्यायालय की डिस्पेंसरी में चिकित्सक का इंतजाम किया है। भविष्य में भी वकीलों के हित में हरसंभव कदम उठाया जाएगा।” मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायालय के मौजूदा भवन में बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति पर चिंता भी जताई और कहा कि पिपल्वाहाना क्षेत्र में बस रहे नये भवन से न्यायाधीशों और वकीलों, दोनों को बड़ी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय के नये भवन में अपेक्षाकृत बड़ी चिकित्सा इकाई स्थापित की जाएगी।





## Dr. Mansukh Mandaviya to Inaugurate International Seminar on “Formalization and Social Security Coverage for Workers in the Informal Sector: Challenges and Innovations”

**New Delhi, Focus News:** Union Minister of Labour & Employment and Youth Affairs & Sports, Dr. Mansukh Mandaviya will inaugurate a two-day international seminar on “Formalization and Social Security Coverage for Workers in the Informal Sector: Challenges and Innovations” on 20-21 January 2025 at New Delhi. Hon’ble Minister of State for Labour & Employment, Sushri Shobha Karandlaje and Secretary (Labour & Employment), Ms. Sumita Dawra will also grace the inaugural session of this technical seminar. This international dialogue is being organized by the Ministry of Labour and Employment of India, in collaboration with the Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) and International Social Security Association (ISSA) at Yashbhoomi - India International Convention and Expo Centre. The technical seminar aims to bring together a diverse group of stakeholders, including policymakers, social security administrators, and experts from social security organizations from countries in the Asia-Pacific region. Over 150 participants will be sharing insights, strategies, and solutions regarding the formalization of informal workers and extension of social security coverage to them. Senior experts from prominent international organizations such as World Bank, United Nations, International Labour



Organization, UN Women, Bill and Melinda Gates Foundation will also share their insights at the event. Senior officers from concerned Ministries/Departments of Government of India, States and UTs and social partners including employers’ and workers’ organizations will also participate. The primary objective of this seminar is to enhance stakeholders’ capacity in extending social protection to informal workers. The sessions will include discussions on pathways and strategies to

promote formalization and enhance social security coverage for vulnerable workers, workers in informal sector and difficult-to-cover groups including through incentives, extend coverage through transforming social security delivery and outreach, digital solutions and communication. Deliberations will also be held on social security coverage extension to promote gender equality and women empowerment, and aspects of health and medical care insurance coverage. The event will

feature exchange of knowledge and experience sharing through technical discussion and sharing of countries’ best practices. Landmark initiatives by India for labour welfare and social protection of workers such as e-Shram portal, National Career Service portal, Employment Linked Incentive (ELI) scheme and Labour Reforms will be showcased. Progress made by ESIC and Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) in advancing social security for formal workers will also be highlighted. The exchange of ideas would enhance capacity of the constituents in the area of extending social protection to informal workers. The seminar will also focus on accurate measurement of progress in social security coverage through improved data collection and reporting. International discourse on this issue is crucial as global reporting on social protection needs harmonization to account for in-kind social protection and welfare measures for more accurate reporting of progress in national and global social protection coverage. In this context, the Ministry of Labour and Employment had initiated in collaboration with ILO, a national data pooling exercise of over 34 Central Government social protection and welfare schemes. Owing to this, India’s social protection coverage doubled from 24.4% to 48.8% in ILO’s latest World Social Protection Report (WSPR) 2024-26.

## Nehru Yuva Kendra Hosts Border Area Youth Exchange Program in Delhi



**New Delhi, Focus News:** The Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) successfully organized the Border Area Youth Exchange Program at the Gandhi Smriti and Darshan Samiti (GSDS) in Rajghat, New Delhi, from January 15 to 19, 2025. The event brought together young people from various border areas across India, providing them with a platform to

interact, learn, and share experiences of unity, peace, and cultural exchange. The five-day program focused on fostering national integration, promoting youth leadership, and creating awareness about the rich cultural diversity of India’s border regions. It saw the participation of over 100 youth representatives from Jammu & Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and Uttarakhand. The program included a mix of cultural activities, workshops, discussions, and visits to significant places in Delhi, including the Raj Ghat Memorial, where Mahatma Gandhi’s legacy of peace and non-violence was highlighted. The program was started with chief guest Dr. Nupur Tiwari, Special Director, NTRI, Dr. Nishant, Director, Cyber Security (MHA), Dr. Jwala Prasad, Director, Gandhi Darshan, Rajghat Sh. Prakash Vaidya, Director (i/c), NYKS, Dr. Lal Singh, State Director, NYKS Delhi.

**Key Highlights of the Program:** Cultural Exchange: Participants showcased their regional traditions, music, and dance, promoting mutual understanding and respect for different cultures.

**Workshops & Sessions:** Focused on leadership development, civic engagement, and strategies for youth empowerment in border areas.

**Visit to National Monuments:** The youth visited prominent historical sites such as Raj Ghat, Qutub Minar, and the National Museum to learn about India’s heritage. **Interactive Discussions:** Experts from various fields led sessions on national security, the importance of youth involvement in governance, and sustainable development in border regions. The closing of the program was done by Sh. Ruchitra Narayan Tyagi, Joint Director Program, NYKS and Dr. Lal Singh, State Director, NYKS Delhi.

## Actor Gul Panag, Boxer Saweety Boora Urges for Road Safety; Lead Nationwide ‘Fit India Sundays on Cycle’



**New Delhi, Focus News:** Well-known actor Gul Panag and Arjuna awardee boxer Saweety Boora rallied behind the ‘Fit India Sundays on Cycle’ campaign saying “it is the only way to build a sporting and fitness culture” in the country as they led more than 500 cyclists at the Leisure Valley park in Gurugram. Road safety was the theme for this week’s nationwide cycling event, which was launched by Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya last month. “I have been associated with the Fit India movement from the time it was launched many years ago.

It is a fantastic initiative by the Sports Authority of India. I think Fit India movement is the only way we will build a sporting and a fitness culture which will lead India into winning more medals in competitive arenas. But we have to start with the fitness culture. That’s where Fit India makes an incredible contribution and Sundays on Cycle is a fabulous initiative. If not on other days we can take out time on Sundays for an easy ride,” Gul Panag said later. “Road safety especially for cyclists is very important. Every year scores of cyclists get deeply injured and some fatally because of automobile drivers not being aware about the cyclists on the road. Cyclists must wear helmets and protective gear like knee guards and elbow guards. I would urge all motorists to be cognizant of cyclists on the streets and look out for them. Please ride safe,” she reminded about road safety. World champion boxer in light heavyweight category, Saweety Boora, who completed the 20km ride meandering through Golf Course Road, AIT Chowk, Arya Samaj Road and Millennium City Centre back to Leisure Valley park, gave the slogan: “Pollution ko punch aur drugs ko right hook kyuki Sundays hai cycling ke liye” (Out punch pollution and deliver a right hook to drugs because Sundays are for cycling). She further added, “This is a great initiative by Fit India. I am very happy to cycle after a long time. Cycling has many benefits including keeping one’s knees in good condition, muscle strength and stamina also improves, which helps in better mobility. It also betters the health of your heart and lungs. Whether you are young or old, cycling is beneficial for overall fitness and remaining healthy.”

## ISKCON Mayapur Elephants to Receive Lifelong Care and Support at Vantara

**New Partnership Formed in the Wake of Tragic Incident Involving an Elephant Fatally Attacking Her Mahout**

**Jamnagar, Focus News:** Vantara, a state-of-the-art animal rescue and rehabilitation organization founded by visionary philanthropist Anant Ambani, is set to welcome two cow elephants, 18-year-old Bishnupriya and 26-year-old LakshmiPriya, from the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) in Mayapur, near Kolkata. This transfer follows a tragic incident last

April when Bishnupriya fatally attacked her mahout, highlighting the urgent need for specialized care and a more suitable environment for their well-being. The transfer project, initiated by Vantara in partnership with ISKCON, has received full approval from the High-Powered Committee, constituted by the Tripura High Court and affirmed by the Supreme Court of India, which is entrusted with rescuing and ensuring safe, stress-free environments for wild animals in distress. At Vantara, Bishnupriya and LakshmiPriya will settle into a permanent home thoughtfully designed to replicate an elephant’s natural habitat. This chain-free environment will provide expert veterinary care, including psychological evaluations and treatments rooted in positive reinforcement training—building trust through rewards and non-coercive methods. They will also benefit from engaging enrichment activities, opportunities to socialize and bond with other elephants, and the compassionate attention of their caretakers, all of which are essential for them to thrive.

ISKCON Mayapur has been keeping LakshmiPriya since 2007 and Bishnupriya



protecting and nurturing all living creatures. Having visited Vantara myself, I could see that the same principles I believe in are followed there. I am confident that Bishnupriya and LakshmiPriya will thrive at Vantara, will soon make new friends, and will live a fulfilling life, experiencing the freedom and joy elephants enjoy in the wild.”

Living in captivity causes significant mental suffering to elephants, who, in the wild, rely on their freedom to roam and bond socially, which ensures their overall

well-being. In captivity, these fundamental needs are often unmet, leading to severe psychological distress that manifests in repetitive behavior, depression, and aggression. At Vantara, the care of rescued elephants extends beyond their physical health, placing equal importance on their mental and emotional recovery. Expert veterinarians and animal psychologists conduct detailed psychological evaluations to identify and address trauma. Vantara’s state-of-the-art facilities, which includes the world’s largest elephant hospital are designed to offer personalized mental health support through positive reinforcement training, stimulating enrichments, and opportunities for social interaction that mimic their natural environment. This holistic approach ensures that rescued elephants not only regain their physical strength but also achieve emotional stability and mental well-being, embodying Vantara’s commitment to their full rejuvenation and improved quality of life.

since 2010, using them for temple rituals and various festival occasions. Animal protection organizations, including People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India and World Animal Protection, had advocated for the release of the ISKCON elephants to a trusted and renowned elephant care facility. PETA India even offered a mechanized elephant for temple rituals in exchange for their transfer to a rescue center. Hrimati Devi Dasi, a senior member of the ISKCON temple and manager for mahouts and elephants in Mayapur, said, “According to our beliefs in ISKCON, everyone is the same spiritual soul inside their outer shell, or material body. We do not make any distinction between species or castes. The different bodies may have different natures; however, the soul within each body is of a spiritual nature and deserves compassion and respect. By treating animals with kindness and respect, we express our devotion to Lord Krishna, who teaches us that true service lies in

## Divya Kala Mela concludes in Vadodara with a Spectacular ‘Divya Kala Shakti’ Performance

**New Delhi, Focus News:** The grand closing ceremony of the Divya Kala Mela took place at Akota Stadium, Vadodara, in the esteemed presence of Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Shri Ramdas Athawale. The event commenced with a mesmerizing dance performance on Ganesh Vandana. Athawale assured every possible support to Divyangjans, emphasizing their integral role in building an Atmanirbhar Bharat. Highlighting the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi, he said, “By 2047, when India would celebrate 100 years of independence, our Divyangjans will inspire the entire world.” He further added that under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, several initiatives have been implemented to promote entrepreneurship, skill development, and financial support for Divyangjans. On this occasion, CMD of NDFDC, Shri Navin Shah, stated that this was the 23rd fair, providing a major platform for the economic empowerment and marketing of Divyangjan products. The 11-day fair, held from 9th - 19th January, 2025, provided a unique platform to encourage Divyang artisans and entrepreneurs to showcase their products and craftsmanship. Over 100 Divyang artisans and entrepreneurs from 20 States and Union Territories participated in the event. Gujarat’s 30 Divyangjans were handed loan sanction letters worth Rs. 1 crore. Motorized tricycles were distributed to 11 Divyangjans through IRCN’s CSR fund, and assistive devices were provided to 14 Divyangjans by ALIMCO. A Job Fair for Divyangjans was also organized on January 17, where appointment letters were distributed to 18 Divyangjans during the closing ceremony.



The ‘Divya Kala Shakti’ cultural programme featured 78 talented Divyang artists from 15 States who enthralled the audience with 36 captivating performances. The event began with a group dance on the song ‘Jay Jay Garvi Gujarat’. Swati from Jammu & Kashmir performed a mesmerizing dance on the song ‘Radha Kaise Na Jale’, from the movie Lagaan. Sanyotani Samadar from Odisha left everyone spellbound with her classical dance performance. The finale saw a patriotic performance by artists from the Blind People’s Association, Ahmedabad. Artists from institutions like Arpan Charitable Trust, Samarth Group, and Parth Group also delivered outstanding performances. Artists from Jammu & Kashmir, Tamil Nadu, and North-Eastern states exhibited their exceptional products, including handicrafts, handlooms, embroidery, and packaged food, thereby promoting the ‘Vocal for Local’ initiative. The cultural performances and diverse food stalls further enhanced the event’s charm.

Dr. Jitendra Singh inaugurates India's First-of-Its-Kind CSIR Mega "Innovation Complex" at Mumbai, dedicates it to Start Ups and Industry stakeholders



New Delhi, Focus News: Union Minister of State (Independent Charge) for Science and Technology, Minister of State (Independent Charge) for Earth Sciences, Minister of State in the Prime Minister's Office, Department of Atomic Energy, Department of Space, and Personnel, Public Grievances, and Pensions, Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first-of-its-kind CSIR Mega "Innovation Complex" at Mumbai on 17th January through virtual mode and dedicated it to StartUps and Industry stakeholders. The new Innovation Complex at Mumbai, inaugurated by the Science & Technology Minister, is a huge state-of-the-art set up spread over nine floors, equipped with 24 "ready-to-move" incubation labs in addition to furnished office and networking spaces for innovative StartUps, MSMEs, industry, and CSIR labs. The Mega facility will provide high-end scientific infrastructure, expertise, and regulatory support to stakeholders including CSIR labs, StartUps, MSMEs, and industry, for the SOP-driven studies necessary for regulatory submissions and compliance. The Complex includes ready-to-move world-class incubation labs and IP/business development support for innovative start-ups, companies partnering with CSIR labs, MSMEs, deep-tech companies from India and abroad, public-funded research institutions, and CSIR labs." Catching up with the excitement of the audience, Dr. Jitendra Singh remarked, "This inauguration is just the beginning. We are excited about the future potential and the immense contributions this Innovation Complex will make to India's growth story." Narendra Modi for his vision, which has enabled India to emerge as a global hub for start-ups and innovation. He described the inauguration of this complex as another landmark step. He reiterated that under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India has emerged as a global hub for start-ups and innovation. Dr. Jitendra Singh said, "We are proud to be the third-largest start-up ecosystem in the world, with over 100 Unicorns that stand as testaments to India's entrepreneurial spirit. This remarkable growth is a reflection of the transformative initiatives and policies introduced by our government to empower the youth and drive economic self-reliance." The Science and Technology Minister further highlighted that the CSIR Innovation Complex Mumbai comes at a pivotal moment in India's start-up journey. According to the Minister, the state-of-the-art facility has been designed to provide incubation and business spaces, enabling start-ups, MSMEs, and industry stakeholders to collaborate with CSIR's network of researchers and innovators. It serves as a bridge between cutting-edge science and its application to address real-world challenges, thereby contributing to the vision of Atmanirbhar Bharat. He called the Innovation Complex a significant milestone for CSIR, representing a giant leap forward in India's innovation landscape and reinforcing the nation's position as a global leader in science and technology. Dr. Jitendra Singh underscored the high-end scientific infrastructure and expertise designed to foster critical translational unmet needs (spanning lab-to-regulator and regulator-to-industry domains) for start-ups, MSMEs, and CSIR labs, while catalyzing faster tech-transfer processes. Dr. Jitendra Singh informed that the IC-Mumbai will provide high-end scientific infrastructure, expertise, and regulatory support to stakeholders (CSIR labs, start-ups, MSMEs, and industry) for the SOP-driven studies necessary for regulatory submissions and compliance. Adding further, he said, "The facility includes ready-to-move world-class incubation labs and IP/business development support for innovative start-ups, companies partnering with CSIR labs, MSMEs, deep-tech companies from India and abroad, public-funded research institutions, and CSIR labs. Informing the industry and start-ups, Dr. Jitendra Singh shared that the complex will function as an innovation and incubation hub to support, collaborate, and partner in key industrial sectors such as healthcare (pharma, biopharma, medtech), chemicals, materials, energy, and other relevant areas of interest to CSIR labs. Speaking about the physical infrastructure of IC-Mumbai, Dr. Jitendra Singh informed that the facility, spread over nine floors, is equipped with 24 "ready-to-move" incubation labs and furnished office and networking spaces for innovative start-ups, MSMEs, industries, and CSIR labs. Concluding his remarks, Dr. Jitendra Singh said, "The inauguration is just the beginning. We are excited about the future potential and the immense contributions this Innovation Complex will make to India's growth story." He added that facilities like the C-ICM embody the spirit of collaboration, innovation, and inclusivity that define the nation's approach to building a self-reliant India. The event was attended by Dr. V.K. Saraswat and Dr. V.K. Paul, Members of NITI Aayog; Dr. N. Kalaiselvi, Secretary of DSIR and DG CSIR; and Dr. Ram Vishwakarma. The inaugural event witnessed participation from industry leaders, foreign delegates from Norway, Switzerland, and Germany, MSMEs, start-ups, and over 1,000 scientists from CSIR labs across India.

Raman Research Institute faculty honored with the Gates-Cambridge Impact Prize 2025

New Delhi, Focus News: Professor Urbasi Sinha, faculty in the Light and Matter Physics theme at the Raman Research Institute (RRI), was honored with the Gates-Cambridge Impact Prize 2025 by the Bill & Melinda Gates Foundation at Cambridge, UK. Prof. Sinha is among the eight winners of Gates-Cambridge's Impact Prize to celebrate its 25th anniversary. She says: "I have seen how the scholarship has evolved over the 25 years and am thrilled to celebrate its anniversary and to be recognised for my work over a similar time span. It is very humbling, but also makes me believe in the impact I can have in the next 25 years." The nomination for her Gates-Cambridge Impact Prize said: "Professor Sinha's vision and dedication are paving the way for a future where quantum computing serves as a catalyst for solving humanity's most pressing issues, embodying the true spirit of science in service of global progress." Prof. Sinha is a researcher in both quantum fundamentals and technologies, and she heads the Quantum Information and Computing (QuIC) lab at RRI an autonomous institute of Department of Science and Technology.

Amit Shah, attends the 20th Raising Day ceremony of NDRF as the Chief Guest in Vijayawada, Andhra Pradesh

New Delhi, Focus News: Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, attended the 20th Raising Day ceremony of the National Disaster Response Force (NDRF) as the Chief Guest in Vijayawada, Andhra Pradesh. During the event, Shri Amit Shah inaugurated many projects and laid the foundation stones for other projects worth approximately Rs 220 crore. These include National South Campus of Institute of Disaster Management (NIDM), the 10th Battalion of the NDRF, and the Regional Response Centre at Supaul Campus. The Home Minister also laid the foundation stone of the new 'Integrated Shooting Range' at the National Police Academy in Hyderabad and inaugurated the Regional Forensic Science Laboratory building in Tirupati. Several dignitaries were present on the occasion, including Andhra Pradesh Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu, Union Minister of Civil Aviation Shri K. Rammohan Naidu, Union Minister of State for Home Shri Bandi Sanjay Kumar, Home Secretary Shri Govind Mohan, and



NDRF Director General Shri Piyush Anand. In his address, Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, said that when natural calamities strike, NDRF comes to the rescue, and when man-made calamities occur, the Narendra Modi government comes to the help. Shri Shah said that in the five years from 2014 to 2019 Andhra Pradesh has faced significant setbacks due to the man-made disaster, affecting the immense potential of the state.

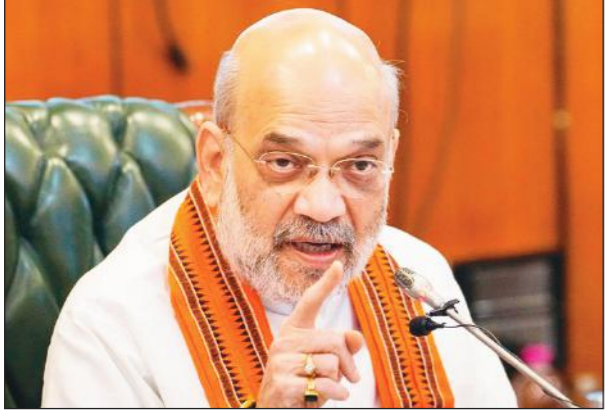
Cabinet approval of Rs. 11,000 Crore for the Visakhapatnam Steel Plant, a move aimed at securing the plant's long-term viability and preserving its status as a symbol of pride for Andhra Pradesh. He also recalled the vision of Amaravati as the state capital, conceptualized by Shri Chandrababu Naidu and inaugurated with a groundbreaking ceremony (Bhoomi Pujan) by Prime Minister Modi. However, he criticized the previous government for neglecting this ambitious project.

Railway Protection Force apprehends 586 bangladeshi and 318 rohingya to prevent illegal migration, since 2021

New Delhi, Focus News: Railway Protection Force (RPF) has successfully apprehended 916 individuals, including 586 Bangladeshi nationals and 318 Rohingya since 2021, showing their commitment to safeguard the nation. In June and July 2024, RPF apprehended 88 Bangladeshi and Rohingya migrants in areas under the Northeast Frontier Railway (NFR). Some of these individuals confessed to entering India illegally and were intercepted while traveling by train to destinations such as Kolkata. In October 2024, reports highlighted that despite increased security measures along the Bangladesh border, illegal migrants continue to infiltrate India, using Assam as a transit route and railways as their preferred mode of travel to reach other parts of the country. These incidents underscore the challenges faced by Indian authorities in monitoring and securing railway networks against illegal infiltration. The use of railways by infiltrators not only facilitates their movement across states but also complicates efforts to detect and prevent unauthorized entry into the country. For considering the above issue, the RPF has intensified its efforts by collaborating with key security agencies such as the Border Security Force (BSF), local police, and intelligence units. This inter-agency approach has significantly enhanced operational efficiency, enabling swift identification and detention of individuals involved in illegal migration. Despite its significant contributions, the RPF is not directly empowered to prosecute apprehended individuals. Instead, detained persons are handed over to police and other authorized agencies for further legal proceedings. In the light of recent political turmoil going on in the neighboring countries such as Bangladesh and Myanmar and geopolitical developments and socio-religious factors in these regions have led to an influx of individuals seeking refuge, employment, and shelter deep within India's hinterlands. It remains a significant concern for national security. While precise statistics on the number of infiltrators using railways are limited, recent reports indicate that illegal migrants often utilize railway networks to transit through regions like Assam and Tripura en route to other parts of India. The Railway Protection Force has risen to the challenge of addressing this critical issue, playing a pivotal role in identifying and apprehending illegal migrants attempting to penetrate India's borders. These individuals are not only a matter of national security concern but are also highly vulnerable to exploitation, including human trafficking for bonded labor, domestic help, prostitution, and even organ harvesting.

Advertisement for 'Pariksha Pe Charcha' featuring a cartoon boy, QR code, and registration information. Text includes: 'WHY TAKE EXAM STRESS KA KHARCHA? When You Can Have Pariksha Pe Charcha', 'IT'S BACK & BIGGER!', 'With whopping 2.26 Crore registrations in 2024', '8th Edition Pariksha Pe Charcha 2025', 'To participate visit: Innovateindia1.mygov.in OR Scan QR Code', and logos for Ministry of Education and myGov.

सिर्फ छह माह में आंध्र प्रदेश के लिये तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई: शाह



अमरावती, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए केवल छह महीनों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शाह, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के दक्षिणी परिसर और विजयवाड़ा के पास राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 10वीं बटालियन के परिसर तथा अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हुडको और विश्व बैंक के माध्यम से अमरावती के विकास के लिए 27,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। शाह ने युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की पिछली सरकार पर कटाक्ष करते हुए आंध्र प्रदेश के लोगों से कहा कि वे 'बर्बाद' हुए पांच वर्ष पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायडू और प्रधानमंत्री मोदी राज्य के विकास के लिए नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर तेजी से प्रयास करते हुए मिलकर काम करेंगे। गृह मंत्री ने कहा, "मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी नीत सरकार आंध्र प्रदेश के विकास के लिए चंद्रबाबू नायडू के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।" शाह ने एनडीआरएफ के बारे में कहा कि आज भारत आपदा प्रबंधन के मामले में विश्व स्तर पर अगुआ के रूप में उभरा है और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। एनडीआरएफ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान काम करता है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 'मानव निर्मित' संकटों के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए आगे आता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के बाद राजग 2025 की शुरुआत में दिल्ली में भी सरकार बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के पूरी तरह से आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में आने तक केंद्र से निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने की अपील की।

आरएसएस ने भाजपा और सहयोगी संगठनों के साथ दो दिवसीय मंथन सत्र आयोजित किया

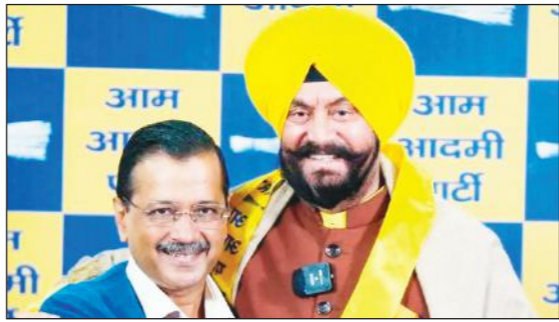
मुंबई, (भाषा) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भाजपा और अन्य सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ विचार-मंथन सत्र आयोजित कर रहा है। एक पदाधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने दो दिवसीय सत्र में शनिवार को भाग लिया, जबकि मंत्री चंद्रकांत पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले व अन्य भाजपा नेता रविवार को मौजूद रहे। भाजपा के अलावा, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य संगठनों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण है। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि यह नियमित बैठक है और संगठन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में विकास की समीक्षा के लिए हर छह महीने में आयोजित की जाती है।

राहुल को नहीं पता कि इंदिरा और नेहरू ने संविधान के साथ कैसे छेड़छाड़ की : नड्डा



अहमदाबाद, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है और वह नहीं जानते कि उनके पिता (राजीव), दादी (इंदिरा) और दादी के पिता (नेहरू) ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के क्या-क्या प्रयास किए थे। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 65 वर्षों तक देश पर शासन किया और उसके नेताओं ने संविधान के साथ छेड़छाड़ कर इसके बुनियादी प्रावधानों को नष्ट करने की कोशिश की। वह भाजपा के 'संविधान गौरव अभियान' में बोल रहे थे। हाल में, केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ एक टिप्पणी में "इंडियन स्टेट" (भारतीय राज व्यवस्था) शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर राहुल पर उन्होंने प्रहार किया। नड्डा ने कहा, "आज हमारे कांग्रेस नेता कहते हैं कि वे 'इंडियन स्टेट (भारतीय राज व्यवस्था) के खिलाफ लड़ रहे हैं।" उन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, न ही उनका इससे कोई लेना-देना है। उन्होंने कहा कि राहुल उन्हें सौंपे गए भाषणों की सामग्री और संदर्भ को समझे बिना उन्हें 'सिर्फ पढ़ते' हैं। राहुल ने हाल ही में कहा था, "भाजपा और आरएसएस ने इस देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है और अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज व्यवस्था से लड़ रहे हैं।" नड्डा ने कहा, "भारत अपना 76 वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है।"

दिल्ली चुनाव: 'एम्बुलेंस मैन' शंटी ने महिलाओं के लिए 'पिक एम्बुलेंस' का वादा किया



नयी दिल्ली, आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह शंटी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में शाहदरा से विधायक चुने जाने पर वह इस क्षेत्र को महिला निवासियों के लिए और बेहतर बनाने के वास्ते 'पिक एम्बुलेंस', कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और उनके बच्चों के लिए 'क्रेच' जैसी सुविधाएं शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। शंटी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए औपचारिक त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) और इलाके की संकरी गलियों में आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम की स्थापना भी उनकी प्रमुख योजनाओं में शामिल है। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने काम के चलते लोगों के बीच 'एम्बुलेंस मैन' के रूप में लोकप्रिय शंटी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि शाहदरा के लोगों की सेवा और महिलाओं की जरूरतों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, "अगर विधायक निर्वाचित हुआ, तो मैं समाज कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के पूरा करूंगा। कामकाजी महिलाओं, अकेली माताओं और बाहर से आई महिला पेशेवरों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाना मेरी प्राथमिकता होगी।" शंटी ने कहा, "इस क्षेत्र में बाहर से आने वाली कई ऐसी महिला पेशेवर हैं, जिन्हें सुरक्षित और किफायती आवास की जरूरत है। उनके बच्चों के लिए क्रेच भी आवश्यक है।"

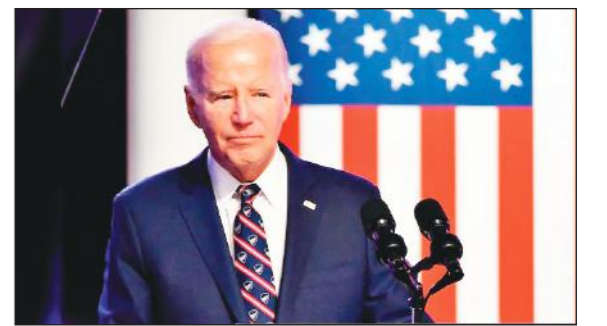
महाकुंभ: मुख्यमंत्री शर्मा ने त्रिवेणी संगम घाट पर स्नान किया



जयपुर, फोकस न्यूज, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट पर स्नान किया तथा मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। शर्मा ने 'एक्स' पर लिखा, 'प्रयागराज में आस्था, श्रद्धा और एकता के महासामगम 'महाकुंभ-2025' में पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की पावन डुबकी लगाने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, लेटे हुए हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन एवं पूर्ण विधि-विधान से पूजन-अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, मंगलमय एवं आरोग्यमय जीवन के लिए प्रार्थना की। यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, शर्मा ने कहा कि देश की प्राचीन संस्कृति और परम्परा समृद्ध है और ऐसी पुरातन एवं वैभवशाली परम्परा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। उन्होंने कहा, "हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के भाव के साथ हम सब को सुख-शान्ति से रहने का संदेश देती है।" उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। शर्मा ने बोट से त्रिवेणी संगम का अवलोकन किया। उन्होंने राजस्थान मण्डप में संत-महात्माओं का अभिनंदन कर उनका आशीर्वाद लिया। शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को भी प्रयागराज महाकुंभ स्थित राजस्थान मण्डप में सुना। मुख्यमंत्री ने कहा, "इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने न केवल देश की वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।"

बाइडन ने रिकॉर्ड बनाया, लगभग 2,500 लोगों की सजा कम की

वाशिंगटन, (एपी) अमेरिकी राष्ट्रपति जो. बाइडन ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह मादक पदार्थों से जुड़े हिंसा रहित अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लगभग 2,500 लोगों की सजा कम कर रहे हैं। 20 जनवरी को अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा और अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों का इस्तेमाल बाइडन ने कैदियों की सजा में छूट और माफी देने के लिए भी किया है। बड़े पैमाने पर इस तरह के क्षमादान और सजा की अवधि कम कर बाइडन ने एक रिकॉर्ड बनाया है। बाइडन ने एक बयान में कहा, "यह कार्रवाई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने, सजा की असमानताओं को ठीक करने और योग्य व्यक्तियों को सलाखों के पीछे बहुत अधिक समय बिताने के बाद अपने परिवारों और समुदायों में लौटने का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" व्हाइट हाउस ने सजा में छूट प्राप्त करने वालों के नाम तुरंत जारी नहीं किए।



इंडियन होटल्स कंपनी का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 29 प्रतिशत बढ़कर 582 करोड़ रुपये पर

नयी दिल्ली, टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लि. (आईएचसीएल) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 29 प्रतिशत बढ़कर 582.32 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में यह लाभ 451.95 करोड़ रुपये था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही में 29 प्रतिशत बढ़कर 2,592 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्तवर्ष 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2,003.64 करोड़ रुपये थी। आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ पुनीत चटवाल ने मजबूत तिमाही प्रदर्शन का श्रेय हवाई और संस्थागत खानपान व्यवसाय के एकीकरण को दिया। उन्होंने कहा, "तीसरी तिमाही भी लगातार 11 तिमाहियों के रिकॉर्ड प्रदर्शन वाली तिमाहियों का हिस्सा है, जिसमें होटल खंड ने 16 प्रतिशत की मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की है...।" आईएचसीएल के पास 360 होटल हैं, जिसमें 13 देशों में और 150 से अधिक स्थानों पर वैश्विक स्तर पर 123 परियोजनाएं शामिल हैं।

# SAY GOODBYE TO EXAM STRESS

with exam tips from PM Modi

Be part of fun discussions & get motivation straight from the top

8th Edition

Pariksha Pe Charcha 2025



To participate

visit: [innovateindia1.mygov.in](https://innovateindia1.mygov.in)

OR Scan QR Code